भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस शोधपत्र

चीन और
दक्षिण प्रशांत

क्षेत्र में भू-राजनीतिक
बदलाव का खुलासा

डॉ. प्रज्ञा पांडे

चीन और दक्षिण प्रशांत

क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलाव का खुलासा

डॉ. प्रज्ञा पांडे

भारतीय वैश्विक परिषद्

भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ एचएन कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद् आज इन-हाउस संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करती है और कई प्रकार के प्रकाशन निकालती है। इसके पास पुस्तकों का एक अच्छा तरह से संग्रहीत पुस्तकालय है, एक सक्रिय वेबसाइट है, और त्रैमासिक जर्नल इण्डिया प्रकाशित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए के पास अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हैं। परिषद् की भारत में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी है।

चीन और दक्षिण प्रशांत: चीन और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलाव का खुलासा

पहली बार प्रकाशित, फरवरी 2023

© Indian Council of World Affair

ISBN: 978-93-83445-72-1 सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति के बिना, इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, एक पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखकों की है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद् सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली 110001, भारत

टेली.: +91-11-2331 7246-49 | फ़ैक्स: +91-11-2331 1208

www.icwa.in

विषय-सूची

सार-संक्षेप	.....	5
1. परिचय	.....	7
2. इंडो-पैसिफ़िक इंडो-पैसिफ़िक के बड़े भू-राजनीतिक मैट्रिक्स में दक्षिण प्रशांत	.....	10
2.1 दक्षिण प्रशांत क्षेत्र	.....	10
2.2 क्षेत्र में व्यापक भू-राजनीतिक परिदृश्य	.....	17
2.3 क्षेत्र की अन्य समस्याएं	.....	19
3. दक्षिण प्रशांत में चीन का ज़ोर: हालिया रुझान	.....	27
3.1 क्षेत्र में चीन द्वारा वित्तपोषित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।	.....	32
3.2 हाल की उच्च स्तरीय बातचीत	.....	38
3.3 सुरक्षा सहयोग के लिए चीन-सोलोमन आइलैंड्सरूपरेखा समझौता: एक विश्लेषण	.....	40
4. चेंजिंग पॉवर डायनामिक्स: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक निहितार्थ	.....	46
5. दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की ओर भारत का दृष्टिकोण	.....	65
निष्कर्ष	.....	68
एंडनोट्स	.....	71

सार-संक्षेप

इंडो-पैसिफ़िक का दक्षिण प्रशांत उप-क्षेत्र हाल के वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का साक्षी रहा है। छोटे प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी'ज़) से बना क्षेत्र, बड़े इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र का एक हिस्सा है। क्षेत्रीय और वैश्विक संवाद में इंडो-पैसिफ़िक निर्माण का बढ़ता महत्व एक प्रमुख कारक रहा है जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण प्रशांत उप-क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित हुआ है। यह क्षेत्र जो काफी हद तक निष्क्रिय रहा है, प्रमुख वैश्विक शक्तियों की ओर से बढ़ती भागीदारी का अनुभव कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में प्रशांत द्वीपों के महत्व और क्षेत्र में छोटे द्वीप राष्ट्रों को बढ़ती चीनी सहायता और समर्थन को देखते हुए, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन का क़द तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की द्वीपीय रणनीति का सक्रिय अनुसरण लंबे समय में शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है। यह पेपर इन मुद्दों की विस्तार से पड़ताल करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे और क्षेत्र में अपने राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक पदचिह्नों को बढ़ाने के लिए बीजिंग के सचेत प्रयास का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है, जो पारंपरिक खिलाड़ियों को हतोत्साहित कर रहा है और क्षेत्र की भू-राजनीति में एक स्पष्ट बदलाव का कारण बन रहा है।

संकेत शब्द: दक्षिण प्रशांत, पीआईसी'ज़, चीन, इंडो-पैसिफ़िक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भू-राजनीति

1. परिचय

'निरंतर गति और गतिशीलता, तात्कालिक सूचना, वैश्वीकरण से प्रभावित' वर्तमान शताब्दी में...अंतरिक्ष और शक्ति पर संघर्ष पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं'।[1] वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य अनिश्चितता और अस्पष्टता के गुण के प्रवाह की स्थिति में है, और निकट भविष्य में ऐसा ही रहने की संभावना है। विशेष रूप से भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच बढ़ते इंटरफेस के भीतर स्पष्टतः पूरे इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र की सुरक्षा एक उल्लेखनीय परिवर्तन की गिरफ्त में है। क्षेत्र की भू-राजनीति, सुरक्षा वातावरण को और जटिल बनाएगी।

क्षेत्रीय और वैश्विक संवाद में इंडो-पैसिफ़िक का बढ़ता महत्व, क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के जटिल और कभी-कभी प्रतिस्पर्धी हितों के साथ क्षेत्र में तीव्र भू-राजनीतिक मंथन के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े प्रशांत क्षेत्र के भीतर, इंडो-पैसिफ़िक के इर्दगिर्द इस चर्चा ने दक्षिण प्रशांत उप-क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित किया है, जो आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस क्षेत्र में छोटे द्वीपीय देश बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड), प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और अपेक्षाकृत कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्षेत्रीय और अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी'ज़) में बाहरी शक्तियों के हितों की विशेषता "संचार के ट्रांसपैसिफ़िक लेन" के लिए उनका रणनीतिक संबंध है, जिसने 1941-45 के प्रशांत युद्ध के दौरान प्रशांत उपनिवेशों और द्वीपों की लड़ाई के लिए 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी लड़ाई को प्रेरित किया।[2] युद्ध के बाद की अधिकांश अवधि में महाशक्तियों के विरोध के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी हद तक निष्क्रिय रहा है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में यह स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है, और कुल मिलाकर वही कारक, यानी प्रशांत आइलैंड्स का भू-रणनीतिक महत्व वर्तमान शक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रमुख प्रबल कारक है।

यह क्षेत्र, जो काफी हद तक अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा है, वर्तमान समय में भारत, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस (विदेशी क्षेत्रों के साथ) से बढ़ती व्यस्तता का अनुभव कर रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र में अब तक का सबसे प्रभावी और विघटनकारी जुड़ाव चीन की ओर से आया है।

हाल के वर्षों में, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में प्रशांत द्वीपों के महत्व और क्षेत्र में छोटे द्वीप राष्ट्रों को चीनी सहायता और सहायता में वृद्धि को देखते हुए, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन का क़द तेजी से बढ़ रहा है। चीन इस क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, जिसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोस में चीन की मजबूत पैठ के कारण क्षेत्रीय खिलाड़ियों - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड - के बीच डर पैदा कर दिया है। "सॉफ्ट पॉवर "कूटनीति पर बीजिंग के प्रयासों ने, क्षेत्र में चीन की सक्रिय उपस्थिति की भविष्य की संभावनाओं और बीजिंग के ऋण संजाल में इन द्वीपों की अरक्षितता के बारे में अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बीच चिंताओं को जन्म दिया है।

तेज भू-राजनीतिक परिवर्तनों को देखते हुए, चीन और अन्य पारंपरिक खिलाड़ियों के बीच एक विकल्प दुविधा के क्षेत्र के बारे में चर्चा का एक प्रमुख विषय है। इस क्षेत्र में चीन की मुखर उपस्थिति का मतलब है कि अन्य सक्रियक, नए और पुराने, अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्नियोजन कर रहे हैं और प्रशांत क्षेत्र में जुड़ाव बढ़ा रहे हैं।

द्वीपों ने हमेशा महान शक्ति की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने छोटे आकार के बावजूद भारतीय और प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप ऐतिहासिक रूप से गेम चेंजर रहे हैं।

महान शक्तिओं की राजनीति में द्वीपों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने छोटे आकार के बावजूद भारतीय और प्रशांत महासागर में द्वीप, ऐतिहासिक रूप से गेम चेंजर रहे हैं। ये छोटे द्वीप इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों द्वारा फ़ॉरवर्ड पॉवर प्रोजेक्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय आर्थिक और भू-रणनीतिक महत्व को देखते हुए, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में द्वीप राष्ट्र धीरे-धीरे बड़े इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर के केंद्र बन रहे हैं।

वाणिज्यवाद, का अतीत और वर्तमान, दर्शाता है कि भू-अर्थशास्त्र, या राज्यों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, महान शक्तियों के उत्थान और पतन के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है।[3] छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के मामले में, इन द्वीपीय देशों में ध्यान केंद्रित करने और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख शक्तियों के अधिक से अधिक हितों को पैदा करने में भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के साथ गुथी हुई है।[4] जबकि ये छोटे द्वीप निवेश की जरूरतों की तलाश में हैं जिन्हें एक या दूसरी प्रमुख शक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे मूल्यांकन करें कि "उनकी रणनीतिक स्वायत्तता के सुरक्षित रहने की संभावना कहाँ अधिक है"।[5]

इस शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य, क्षेत्र में चीन की बढ़ती कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति के आलोक में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक बदलावों का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य पीआईसी'ज़ के साथ अपने जुड़ाव में प्रमुख खिलाड़ियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है।

2. इंडो-पैसिफ़िक इंडो-पैसिफ़िक के बड़े भू-राजनीतिक मैट्रिक्स में दक्षिण प्रशांत

2.1 दक्षिण प्रशांत क्षेत्र

इंडो-पैसिफ़िक का दक्षिण प्रशांत उप-क्षेत्र "एशिया और अमेरिका के बीच रणनीतिक सीमा रेखा" के रूप में कार्य करता है।[6] प्रशांत द्वीपों में द्वीपों के तीन प्रमुख समूह शामिल हैं: मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। प्रशांत द्वीप देश (पीआईसी'ज़) शब्द यहां आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर में बिखरे हुए चौदह देशों के संबंध में है। ये हैं कुक आइलैंड्स, फ़िज़ी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु। ये निश्चित रूप से एक समान समूह वाले देश नहीं हैं, जिनमें जातीय समूहों, संस्कृति, भाषाओं, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और विभिन्न अन्य अंतरों के विविध समुच्च्य हैं। ये हैं- संसदीय लोकतंत्र (कुक आइलैंड्स और फ़िज़ी), संवैधानिक परिसंघ (माइक्रोनेशिया), गणराज्य (किरिबाती, नाउरू, समोआ, वानुअतु), संवैधानिक राजतंत्र (पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तुवालू) और संसदीय राजशाही (टोंगा)। चौदह पीआईसी'ज़ में से नौ संप्रभु हैं - किंगडम ऑफ़ टोंगा, फ़िज़ी, किरिबाती, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू और वानुअतु। अन्य बड़े राष्ट्रों के साथ मुक्त संघ में हैं - जिसका अर्थ है कि उनकी विदेशी और रक्षा नीतियों का प्रबंधन बड़े राष्ट्रों द्वारा किया जाता है।

पीआईसी'ज़ निश्चित रूप से एक समान समूह वाले देश नहीं हैं, जिनमें जातीय समूहों, संस्कृति, भाषाओं, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और विभिन्न अन्य अंतरों के विविध समुच्च्य हैं।

कुक आइलैंड्स और नीयू न्यूजीलैंड के साथ मुक्त संघ में हैं, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ, अमेरिका के साथ।[7] अधिकांश देशों में, सरकार की एक लोकतांत्रिक शैली पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में है।

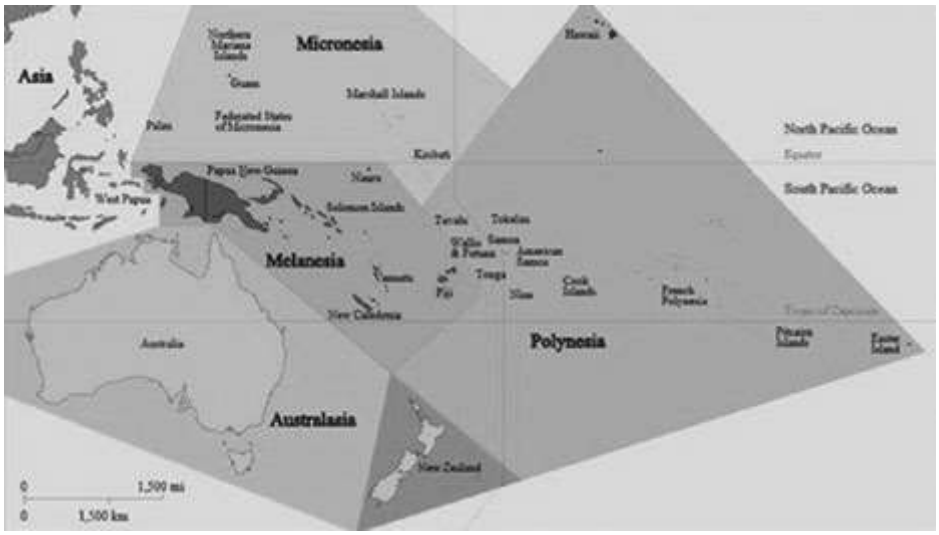

चित्र 1: दक्षिण प्रशांत में तीन प्रभागों को दर्शाता हुआ मानचित्र

तालिका सं. 1

क्र.सं.	देश	क्षेत्रफल	ईईज़ेड	जनसंख्या	राजनीतिक प्रणाली	आर्थिक क्षेत्र
	कुक आइलैंड्स	240 वर्ग किमी	1.8 मिलियन वर्ग किमी	13,100	संसदीय लोकतंत्र - न्यूजीलैंड के साथ मुक्त संघ	पर्यटन, मोती उद्योग, मत्स्य पालन
	फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया	702 वर्ग किमी	2.9 मिलियन वर्ग किमी	103,000	अमेरिका के साथ मुक्त संघ में संवैधानिक परिसंघ	कृषि, पर्यटन, मछली पकड़ना, सेवाएं
	किरिबाती	810 वर्ग किमी	3.6 मिलियन वर्ग किमी	114,000	एक कार्यकारी अध्यक्ष के साथ गणतंत्र	कृषि, मत्स्य पालन
	मार्शल आइलैंड्स	180 वर्ग किमी	2.1 मिलियन वर्ग किमी	55,000	अमेरिका के साथ मुक्त संघ में संवैधानिक सरकार	पर्यटन, निर्वाह कृषि, मत्स्य पालन
	नाउरू	21 वर्ग किमी	320,000 वर्ग किमी	10,800	एक कार्यकारी राष्ट्रपति वाला गणतंत्र	फॉस्फेट खनन, मछली पकड़ने, अपतटीय प्रसंस्करण केंद्र और सेवा प्रदाताओं से राजस्व
	नीयू	260 वर्ग किमी	390,000 वर्ग किमी	1470	न्यूजीलैंड के साथ मुक्त संघ में पूर्ण स्वशासन	निर्वाह कृषि, मछली पकड़ना, पर्यटन
	पलाऊ	460 वर्ग किमी	600,900 वर्ग किमी	18,000	अमेरिका के साथ मुक्त संघ में	पर्यटन, सेवाएं, निर्वाह कृषि,

					संवैधानिक सरकार	मत्स्य पालन
	तुवालु	30 वर्ग किमी	757,000 वर्ग किमी	11,000	हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अधीन संवैधानिक राजतंत्र	कृषि और मत्स्य पालन

स्रोत: पीआईएफ़ वेबसाइट

क्र.सं.	**देश**	**क्षेत्रफल**	**ईईज़ेड**	**जनसंख्या**	**राजनीतिक प्रणाली**	**आर्थिक क्षेत्र**
	फ़िज़ी	18.3 हज़ार वर्ग किमी	1.26 मिलियन वर्ग किमी	890,000	संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य	कृषि, विनिर्माण, खनन, पशुधन खेती, पर्यटन, मछली पकड़ने, चीनी, निर्माण।
	फ़्रेंच पोलिनेशिया	4000 वर्ग किमी	4.7 मिलियन वर्ग किमी	268,270	फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत विदेशी देश - संसदीय लोकतंत्र	पर्यटन, मोती उद्योग
	न्यू कैलेडोनिया	18.6 हज़ार वर्ग किमी	1.4 मिलियन वर्ग किमी	268,767	मैन्डेटिड कॉलेजिएट सरकार	निकल उद्योग, खनन, फ्रांस से वित्तीय हस्तांतरण, पर्यटन, निर्माण
	पापुआ न्यू गिनीआ	463 हज़ार वर्ग किमी	3.1 मिलियन वर्ग किमी	7.7 मिलियन	संवैधानिक राजतंत्र	कृषि, लकड़ी, खनन, सोना, तांबा, चांदी), प्राकृतिक गैस
	टोंगा	720 वर्ग किमी	700,000 वर्ग किमी	104,000	राष्ट्रीय राजशाही	कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन
	सोलोमन आइलैंड्स	27.9 हज़ार वर्ग किमी	1.6 मिलियन वर्ग किमी	588,000	हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अधीन संवैधानिक राजतंत्र	कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी
	वानुअतु	12.2 हज़ार वर्ग किमी	680,000 वर्ग किमी	269,000	गणतंत्र	कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन,

						पशुपालन

स्रोत: पीआईएफ़ वेबसाइट

रणनीतिक रूप से स्थित छोटे द्वीप राष्ट्र (नाउरू का कुल भूमि क्षेत्र 21 वर्ग किमी है।), छोटी आबादी (नीयू की कुल जनसंख्या लगभग 1470 है)[8], प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत, अपेक्षाकृत कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित क्षेत्र, विशेष रूप से इंडो-पैसिफ़िक निर्माण की लोकप्रियता को देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इन दूर स्थित द्वीप राष्ट्रों की विशेषता छोटी आबादी, जिसमें क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 6.6 मिलियन होने का अनुमान है[9], इसके साथ खराब बुनियादी ढांचे, बाजारों से लंबी दूरी, दूरसंचार और परिवहन की उच्च लागत, आयात पर भारी निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम हैं।

कई द्वीप देशों की अर्थव्यवस्था एक या कुछ वस्तुओं पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, चीनी, पशुधन खेती और कुछ मामलों में खनन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश द्वीपों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा निर्वाह कृषि में लगा हुआ है, और कई देशों में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है।[10] इस क्षेत्र से प्रमुख निर्यात में उच्च मूल्य वृक्षारोपण इमारती लकड़ी, स्थानीय सूखे फल और प्रसंस्कृत फल शामिल हैं। टोंगा और समोआ के पास अच्छी मिट्टी और कृषि क्षमता है। किरिबाती और तुवालु में सीमित संसाधन आधार और प्रमुख आंतरिक परिवहन समस्याएं हैं। कुक आइलैंड्स से प्रमुख कृषि उपज और निर्यात में अनानास, संतरा और केला शामिल हैं; न्यू गिनीआ से एक प्रमुख निर्यात कॉफी है; समोआ और सोलोमन आइलैंड्स से कोको और फ़िज़ी में बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग है।[11]

तालिका सं. 2

क्षेत्र	प्रमुख कृषि उत्पाद
मेलानेशिया	उच्च मूल्य वाली वृक्षारोपण इमारती लकड़ी, उचित व्यापार चीनी, बोतलबंद पानी, वर्जिन नारियल का तेल, नारियल के उत्पाद (सौंदर्य प्रसाधन, फर्नीचर, आदि), ताजा टूना (साशिमी), 'एकल स्रोत' कोको और कॉफी, कावा, ताजे फल और सब्जियां, स्थानीय सूखे फल, ताजे फूल, संरक्षित मसाले, ऑर्गेनिक बीफ़, मोती
पोलिनेशिया	वर्जिन नारियल का तेल, सौंदर्य प्रसाधन, काले मोती, नोनी रस, सूखे जैविक फल, मसाले, एकल स्रोत कोको और कॉफी कावा, ताजे फल और सब्जियां (विशेष रूप से स्कैश), स्थानीय सूखे फल, ताजा मछली, वेनिला
माइक्रोनेशिया	वर्जिन नारियल का तेल, नारियल उत्पाद, आयात प्रतिस्थापन

स्रोत: वेस्ली मॉर्गन और टेस न्यूटन कैन, "एक्टिवेटिंग ग्रेटर ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पेसिफ़िक आईलैंड कंट्रीज़", पॉलिसी ब्रीफ, ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट, जून 2020, पृ. 9

इस क्षेत्र में अंतर-द्वीप व्यापार बहुत सीमित है। द्वीप राज्यों से क्षेत्रीय देशों - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को महत्वपूर्ण निर्यात में शामिल है - पापुआ न्यू गिनीआ से सोना और कच्चा पेट्रोलियम; फ़िज़ी से सोना, कपड़े, बिस्कुट और बोतलबंद पानी; और सोलोमन आइलैंड्स से सोना और इमारती लकड़ी। क्षेत्र के बाहर, यूरोप प्रशांत निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है, विशेष रूप से प्रसंस्कृत टूना और मेलानेशियन राज्यों से कृषि निर्यात के लिए। इसके अलावा, अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में अमेरिका, जापान, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ राष्ट्र शामिल हैं। चीन, मुख्य रूप से आयात और निवेश के मामले में, धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बनता जा रहा है।

पीआईसी'ज़ का महत्व उनके संसाधन संपन्न ईईजेड'ज़ में बहुत अधिक है, जो मत्स्य पालन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), हाइड्रोकार्बन्स और समुद्री तल खनिजों जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का आकर्षक स्रोत बन सकता है। कुछ पीआईसी'ज़ में ऐसे ईईजेड हैं जो कुल मिलाकर भू-भाग और भारत के ईईजेड से बड़े हैं । सबसे छोटे देशों में से एक किरिबाती के पास ही 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का ईईजेड है।[12]

चित्र 2: प्रशांत द्वीप देश और उनके ईईजेड'ज़
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)।

उनके भूगोल को देखते हुए, पीआईसी'ज़ में 80 प्रतिशत से अधिक आबादी समुद्र तट के 1.5 किमी के भीतर रहती है। यह क्षेत्र बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, चक्रवात, आंधी, तूफान और बाढ़ से बढ़ती चुनौतियों; बढ़ती तटीय बाढ़; प्रतिक्रिया करने की सीमित क्षमता के साथ मिलकर, मिट्टी की लवणता और कटाव, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, का सामना करता है। जैसे-जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, प्रवाल भित्तियाँ जो द्वीपों की रक्षा करती हैं और मत्स्य पालन को बढ़ावा देती हैं, का विरंजन हो रहा है और समुद्र तेज़ी से गर्म होता जा रहा है।

पीआईसी'ज़ का महत्व उनके संसाधन संपन्न विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड'ज़) में बहुत अधिक है, जो मत्स्य पालन, एलएनजी, हाइड्रोकार्बन्स और समुद्री तल खनिजों जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के आकर्षक स्रोत हो सकते हैं

ये जोखिम, गरीबी, लोगों के तेजी से आवागमन और बाहरी द्वीपों से शहरी क्षेत्रों और विकसित देशों की ओर पलायन की अन्य समस्याओं के अलावा हैं, जिनके परिणामस्वरूप मानव संसाधनों की कमी हो रही है।

2.2 क्षेत्र में व्यापक भू-राजनीतिक परिदृश्य

भू-राजनीति को मोटे तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक आयाम वाली भौगोलिक संस्थाओं के नियंत्रण के लिए संघर्ष और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी भौगोलिक संस्थाओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।[13] गियरॉइड ओ'तुआथाइल ने अपनी क्रिटिकल जिओपॉलिटिक्स (1996) में 'भू-शक्ति' की अवधारणा का परिचय दिया है, उनका तर्क है कि "भूगोल, शक्ति के बारे में है", सीमाओं, अंतरिक्ष और अधिकार पर मानव संघर्ष का एक सदैव-बदलता मानचित्र। "यह सत्ता पर प्रतिस्पर्धा करने वाले सत्ताधीशों के बीच संघर्ष के इतिहास का एक उत्पाद है, जो स्थान पर कब्जा करते हैं और प्रशासन करते हैं।[14] उनका तर्क है कि वैश्विक राजनीति अंतरिक्ष पर सतत संघर्ष की विशेषता है। दक्षिण प्रशांत में द्वीपों, विशेष रूप से चीन के साथ प्रमुख शक्तियों की जुड़ाव में वृद्धि का, इस आलोक में विश्लेषण किया जा सकता है क्योंकि यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को संभावित रूप से बदल रहा है। इस क्षेत्र में चीन की हालिया रुचि पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देती दिख रही है, जिससे क्षेत्रीय खिलाड़ियों में आशंका पैदा हो रही है।

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, जिसे आमतौर पर शांत बैकवाटर्स माना जाता था, जहां तक क्षेत्र के भू-रणनीतिक वातावरण का संबंध है, गंभीर परिवर्तन अनुभव कर रहा है।[15] दक्षिण प्रशांत, अभी तक, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड-संयुक्त राज्य अमेरिका (एएनजेडयूएस) त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन के अधीन प्रबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस') के प्रभाव का एक क्षेत्र माना जाता था।[16]

लंबे समय तक, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, जहाँ तक पश्चिमी शक्तियों का संबंध था, दक्षिण प्रशांत भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक "बैकवाटर" में पीछे चला गया।[17] हालाँकि, हाल के वर्षों में स्थिति बदलती रही है; ये द्वीप न केवल चीन के बीआरआई का हिस्सा हैं बल्कि अमेरिका की स्वतंत्र और खुली हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।[18] इसके साथ-साथ, भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की गहनता के मद्देनजर क्षेत्रीय देश इस क्षेत्र में अपने सक्रिय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की मौजूदा अरक्षितता बढ़ रही है। जैसे-जैसे वैश्विक ध्यान इंडो-पैसिफ़िक की ओर जा रहा है, दक्षिण प्रशांत उप-क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

ग़ौर करने वाली बात यह है कि, वैश्विक के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण आज प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती रणनीतिकप्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा के बीच अत्यधिक आवेशित है। यूक्रेन में संकट, अमेरिका-चीन के बीच होड़, क्षेत्र में, महामारी के बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में और गिरावट आई है, और निश्चित रूप से, एक प्रमुख कारक, जो हाल के भू-राजनीतिक बदलावों को प्रभावित करने में परिणामी रहा है, वह चीन की असममित वृद्धि और पूरे क्षेत्र में इसकी बढ़ती पकड़ रहा है। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि चीन को संतुलित करने के एक स्पष्ट प्रयास में, जहां क्षेत्र तेजी से सुरक्षित हो रहा है और अन्य खिलाड़ी अपनी विदेश, सुरक्षा और सैन्य नीतियों में तेजी से सक्रिय रुख अपना रहे हैं। इस सबके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति में हुई है जहां क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन अनिश्चित दिखायी देता है।

इन घटनाक्रमों के आलोक में, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस क्षेत्र में चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में मुखर रहे हैं और अपने प्रशांत पड़ोस में अपनी भूमिका को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन को संतुलित करने के एक स्पष्ट प्रयास में, क्षेत्र अन्य खिलाड़ियों के साथ तेजी से सुरक्षित हो रहा है, अपनी विदेश, सुरक्षा और सैन्य नीतियों में तेजी से सक्रिय रुख अपना रहा है।

इस प्रकार, दक्षिण प्रशांत धीरे-धीरे व्यापक इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के भीतर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र-बिंदु बनता जा रहा है।

2.3 क्षेत्र की अन्य समस्याएं

जैसा कि पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, यह क्षेत्र शक्ति प्रतिद्वंद्विता का एक नया स्वरूप देख रहा है जहां सामर्थ्य की अलग-अलग कोटि वाली शक्तियाँ प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करती रही हैं, जो काफी हद तक क्षेत्र के रणनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा। साथ ही यह क्षेत्र कई अन्य चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। चारों ओर पानी वाले इन देशों का भूगोल एक खजाना है और साथ ही, उन्हें गैर-पारंपरिक कोणों से विभिन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील भी बनाता है।

शीत युद्ध के बाद की दुनिया में, पारंपरिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की अवधारणा की समझ में बढ़ती स्वीकार्यता के साथ महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि सुरक्षा को व्यक्तिपरक, लोचदार और अनिवार्य रूप से विवादित अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए। दूसरे राष्ट्र से उभरने वाले राज्य के लिए अस्तित्वगत खतरों की अनुपस्थिति के रूप में सुरक्षा की अवधारणा की गंभीर आलोचना हुई है। राष्ट्र के लिए अस्तित्वगत खतरों की अनुपस्थिति के रूप में सुरक्षा की अवधारणा की दूसरे राज्य से उभरने की गंभीर आलोचना हुई है। लोगों

और राज्य की सुरक्षा, अस्तित्व और भलाई के लिए गैर-पारंपरिक जोखिमों ने, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, संक्रामक रोगों, भोजन की कमी, अनियमित प्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी

जैसे गैर-सैन्य स्रोतों से और इसी प्रकार के अन्य पार देशीय अपराधों से पैदा होते हैं, प्रधानता प्राप्त कर ली है।

सुरक्षा की अवधारणा पर समकालीन सैद्धांतिक बहस के उद्भव को 1980 के दशक में, बढ़े हुए शीत युद्ध के तनाव की अवधि के दौरान रिचर्ड उल्मैन (1983) के लेखन रिडिफ़ाइनिंग सिक्योरिटी एंड बैरी बुज़ान की पीपुल, स्टेट एंड फियर में (1983,1991) में देखा जा सकता है। उल्मैन ने सुरक्षा के लिए अत्यधिक सैन्य-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना की, जिसका उन्होंने तर्क दिया, "वास्तविकता की एक पूरी तरह से झूठी छवि व्यक्त करता है।"[19] बुज़ान के लिए सुरक्षा "सिर्फ राज्य के बारे में नहीं बल्कि सभी मानव सामूहिकताओं से संबंधित है", और मानव सामूहिकता की यह सुरक्षा पाँच प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के कारकों से प्रभावित थी।[1] संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल ने धमकी, चुनौती और परिवर्तन (2004) में सुरक्षा चुनौतियों के छह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की: "आर्थिक और सामाजिक खतरे; अंतर-राष्ट्रीय संघर्ष; आंतरिक संघर्ष; परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार; आतंकवाद; और पार देशीय संगठित अपराध "।[20]

शांति और सुरक्षा के लिए खतरे बहुआयामी और बहुमुखी हो गए हैं, जिसमें पारंपरिक, यथार्थवादी "राज्य केंद्रित" और गैर-पारंपरिक चुनौतियां दोनों शामिल हैं, जो अक्सर प्रकृति में पार देशीय होती हैं। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संरचनात्मक आर्थिक संकट और मानव जाति के लिए सार्वभौमिक खतरा दोनों किसी एक राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और क्षमता से परे होते हैं। संक्षेप में, सुरक्षा के लिए खतरे और उनसे निपटने के तरीके दोनों ही प्रकृति में वैश्विक हो गए हैं।

[1] हालाँकि, शीत युद्ध के बाद 1991 में प्रकाशित पुस्तक के दूसरे संस्करण में इनमें से सैन्य कारक को शामिल नहीं किया गया है। बुज़ान, बैरी, "पीपल स्टेट्स एंड फियर: एन एजेंडा फ़ॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज इन पोस्ट-कोल्ड वॉर एरा", दूसरा संस्करण, हार्वेस्टर व्हीटशेफ, न्यूयॉर्क (1991) देखें।

शांति और सुरक्षा के लिए खतरों की प्रकृति ने भी एक नया आयाम ग्रहण कर लिया है क्योंकि यह बहुआयामी और बहुमुखी हो गए हैं। न केवल पारंपरिक, यथार्थवादी "राज्य-केंद्रित" खतरों से बल्कि गैर-पारंपरिक चुनौतियों से भी चुनौती दी जाती है जो अक्सर प्रकृति में पार देशीय होती हैं।

दक्षिण प्रशांत के द्वीपीय देश अक्सर चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूस्खलन और सूखे का सामना करते हैं। पीआईसी'ज़ द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक में जलवायु परिवर्तन और संबंधित प्रभाव शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन को क्षेत्र में लोगों की आजीविका, सुरक्षा और कल्याण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में पहचाना गया है। समुद्र के बढ़ते स्तर से द्वीपीय राज्यों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन और तटीय मत्स्य पालन के अति-दोहन के कारण होने वाली बढ़ती समस्या के कारण भविष्य में खाद्य सुरक्षा एक चिंता का विषय हो सकती है। उनके भूगोल को देखते हुए, प्रशांत द्वीप के अधिकांश देश विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सूनामी आदि से प्रभावित होने की चपेट में रहते हैं। नई दिल्ली, भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2018 के दूसरे संस्करण में, फ़िज़ी के प्रतिनिधि, अटॉर्नी-जनरल और अर्थव्यवस्था मंत्री, अयाज़ सैयद-खय्यूम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन के लिए एक तत्काल खतरा प्रस्तुत करता है, और पीआईसी'ज़ जैसे जलवायु संवेदनशील देशों को अधिक वित्त और सतत विकास सहायता उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण मिट्टी की लवणता में लगातार वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो विशेष रूप से निचले स्तर के कमजोर देशों में एक प्रमुख चुनौती है, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को खतरा, पुनर्वास की समस्याओं और अन्य मुद्दों को जन्म दे रहा है।[21] उन्होंने विशेष रूप से "किरिबाती सरकार द्वारा फ़िज़ी में भूमि की खरीद के मामले पर प्रकाश डाला,

जो समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी।[22] फ़िज़ी के प्रधान मंत्री फ्रैंक बैनिमारामा ने तर्क दिया कि प्रशांत द्वीपों के पास अपना नैतिक अधिकार है क्योंकि कमजोर राज्य दुनिया को अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक आक्रामक जलवायु कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं'।[23] जुलाई 2022 में 51वें प्रशांत द्वीप फ़ोरम (पीआईएफ़) नेताओं के शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने ब्लू पैसिफ़िक महाद्वीप के लिए 2050 की रणनीति का समर्थन किया, एक क्षेत्रीय रणनीति जो "ब्लू पैसिफ़िक" नैरेटिव के आधार पर प्रशांत क्षेत्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। रणनीति, जनकेंद्रित विकास, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, महासागर और प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।[24]

इससे पहले, नाउरू में 2018 में 49वें पीआईएफ़ शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय देशों द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय सुरक्षा पर बोई घोषणा ने, सुरक्षा की अवधारणा और मानव सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पार देशीय अपराधों और साइबर सुरक्षा के प्राथमिकता वाले मुद्दों को "बहमुखी चुनौतियों" के साथ "सर्व समावेशी" के रूप में मान्यता दी। घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया कि इन चुनौतियों का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग को महत्व दिए जाने की जरूरत है। इसने जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण का जवाब देने के लिए सदस्यों के बीच घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।[25] घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुरक्षा की विस्तारित अवधारणा की क्षेत्रीय स्वीकृति है।

उभरती भू-राजनीति का विश्लेषण करते समय क्षेत्र की आंतरिक डायनामिक्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र के कई छोटे द्वीपों में भी नाजुक सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं। फ्रेंच पोलिनेशिया और न्यू कैलेडोनिया में अन्तर्जात अस्थिरताएं हैं। वे स्थानीय निर्वाचित सरकार के साथ-साथ पोस्ट किए गए फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा प्रशासित होते हैं। विरोध और हिंसा और अस्थिर सरकारों के इतिहास के साथ

विकसित भू-राजनीति का विश्लेषण करते समय क्षेत्र की आंतरिक डायनामिक्स को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र के कई छोटे द्वीपों में नाजुक सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं भी हैं।

उनके पास जातीय रूप से विविधपूर्ण आबादी है।[26] सोलोमन आइलैंड्स का अंतर-द्वीप तनावों का इतिहास रहा है। देश के कुछ हिस्सों में प्रांतीय सरकारों के केंद्र सरकार के साथ वर्षों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।[27] मलैता प्रांत में भी स्वायत्तता के स्वर उठे हैं, जो वर्षों से काफी हद तक केंद्र की ओर से उपेक्षित महसूस करते हैं। देश ने नवंबर 2021 में सोगावारे प्रशासन के बीजिंग समर्थक रुख के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सरकार-विरोधी विरोध भी देखा। इससे पहले 2006 में भी देश में दंगे हुए थे। दूसरी ओर, टोंगा ने 2006 में चीनी-विरोधी विरोध देखा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा अल्पकालिक हस्तक्षेप किया गया। 2009 में, पीएनजी को कुछ हिस्सों में चीनी-विरोधी आंदोलन का अनुभव हुआ। इसलिए, "क्षेत्र में प्रशांत आइलैंड्सऔर चीनियों के बीच संघर्ष की वापसी की संभावना बनी हुई है।[28] पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वानुअतु असाधारण भाषाई और समूह विविधता की विशेषता के साथ राज्य-सूचनाएं हैं जो राष्ट्रीयता की कमजोर चेतना को जन्म देती हैं।

नाउरू ने सरकार के लगातार परिवर्तन और आपातकाल की स्थिति का अनुभव किया है।[29] फ़िज़ी ने अतीत में तख्तापलट के साथ सैन्य हस्तक्षेप के साथ-साथ आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता देखी है।[30]

तेल और गैस के स्रोतों से दूर स्थित इन देशों के लिए ऊर्जा एक अन्य प्रमुख प्राथमिकता है। अक्षय ऊर्जा, पवन और सौर की संभावना को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक स्थायी तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। इनमें से अधिकांश द्वीपों में ऐसी ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता नहीं है और इसलिए,

यह एक अन्य क्षेत्र है जहां उन्हें ऐसी विशेषज्ञता रखने वाले राष्ट्रों की ओर से तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। भारत ने इस क्षेत्र में पीआईसी को सहायता प्रदान की है। पीआईसी में सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का एक उल्लेखनीय उदाहरण में राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज में फ़िज़ी, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालु, समोआ, किरिबाती और नाउरू की बुजुर्ग महिलाओं के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।[31] इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य "दादी-नानियों को प्रशिक्षण के माध्यम से सौर इंजीनियरों में बदलना", उनके रहने के गांवों में सौर प्रकाश और बिजली लगवाना और इसका रखरखाव करना है।[32] अतीत में, भारत ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन में क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र के छोटे द्वीप राज्यों की मदद करने के उद्देश्य से भारतीय अनुसंधान संगठन टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के माध्यम द्वारा 2007 में सुवा, फ़िज़ी में 'पीआईएफ़ देशों के लिए सतत विकास' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की थी।[33] खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की समस्या को समुद्री संसाधनों के उचित उपयोग से निपटा जा सकता है, क्योंकि पीआईसी'ज़ को बड़े समुद्री देशों के रूप में माना जाना चाहिए न कि छोटे देशों के रूप में।

यह क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है लेकिन अधिकांश द्वीपों में उन्हें निकालने की क्षमता नहीं है।" अधिकांश क्षेत्रों के माल निर्यात को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्राथमिक संसाधन निष्कर्षण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिनके पास उन संसाधनों तक पहुंचने के लिए साधन और तकनीकी जानकारी है। खनिज, लकड़ी और मछली जैसे संसाधनों के निर्यात से उत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभों का बड़ा हिस्सा उन फर्मों को अर्जित करने के लिए जाता है। कम स्थानीय प्रसंस्करण, और सीमित प्रभावशीलता की कर व्यवस्था के साथ, मेजबान देश के लिए रोजगार और वित्तीय लाभ न्यूनतम हैं"।[34] इस क्षेत्र का विश्व के टूना उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है; हालाँकि, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कैच को बरकरार रखा जाता है।

"सुदूर देशों और प्रशांत राज्यों के जहाजों द्वारा अधिकांश टूना पकड़ी जाती है, मछली पकड़ने के लाइसेंस बेचकर आय अर्जित करती हैं।"[35]

इनके अलावा, क्षेत्र में एक और हालिया तनाव क्षेत्रवाद को चुनौती दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंच पैसिफ़िक आईलैंड फ़ोरम (पीआईएफ़) संकट का सामना कर रहा है। पीआईएफ़, 1971 में गठित, एक बहुपक्षीय मंच, 'सामान्य पहचान और उद्देश्य की भावना' पर आधारित,[2] दक्षिण प्रशांत में प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। यह छोटे और सुदूर स्थित देशों को सुने जाने का अवसर प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। जुलाई 2022 में 51वीं शिखर बैठक से ठीक पहले, किरिबाती ने फ़ोरम से हटने के अपने इरादे की घोषणा की। वर्तमान संकट फरवरी 2021 में पीआईएफ़ (किरिबाती, नाउरू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और पलाऊ) के पांच माइक्रोनेशियाई सदस्यों की घोषणा पर पीछे जाता है कि उन्होंने पीआईएफ़ के नए महासचिव (हेनरी पूना, पोलिनेशिया क्षेत्र से कुक आइलैंड्सके पीएम) की नियुक्ति के

[2] फ़ोरम के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फ़िज़ी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यूगिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।

मुद्दे पर संगठन छोड़ने का फैसला किया है, किरिबाती उनमें से एक था। किरिबाती की वापसी की घोषणा, सदस्य देशों के बीच दरार को दूर करने के लिए पिछले एक वर्ष में किए गए प्रयासों के लिए एक झटके के रूप में है (चूंकि माइक्रोनेशियन सदस्यों[3] ने फ़ोरम से बाहर निकलने के अपने इरादे की घोषणा की थी)। फ़ोरम में यह विभाजन समूह के भीतर उत्तर और दक्षिण के बीच एक निहित तनाव को भी सामने लाया था।[36]

ऐसा लगता है कि समूह में दक्षिण, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ़िज़ी सहित बड़े खिलाड़ियों का वर्चस्व है।[4] माइक्रोनेशियन देशों को लगता है कि कैनबरा और वेलिंगटन दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं।

इन मुद्दों के साथ-साथ कोविड महामारी के दो वर्ष से अधिक समय तक चली चुनौतियों और प्रमुख शक्तियों पर बढ़ते कर्ज के साथ इन द्वीपीय राज्यों के लिए गंभीर आर्थिक चिंताएँ पैदा कर दी हैं। महामारी और स्थानीय संरोधन उपायों ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तनाव में डाल दिया है। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र, यानी पर्यटन, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2020 में इस क्षेत्र के आउटपुट में औसतन 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। पीआईसी'ज़ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए दुनिया भर में सबसे कमजोर देशों में से एक है और जलवायु संबंधी घटनाओं से बाहरी झटके जारी हैं। आर्थिक संकुचन, पर्यटन राजस्व में कमी, और प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों ने आम तौर पर 2021 में राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया। महामारी के कारण

[3] दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में द्वीपों के तीन समूह हैं: माइक्रोनेशिया: किरिबाती, नाउरू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप और पलाऊ पोलिनेशिया: कुक आइलैंड्स, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, फ्रेंच पोलिनेशिया मेलनेशिया: फ़िज़ी, वानुअतु, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स

[4] छोटी आबादी और अर्थव्यवस्थाओं के साथ, दक्षिण में अपने बड़े, अधिक प्रभावशाली और आर्थिक रूप से बड़े पड़ोसियों द्वारा माइक्रोनेशियन राष्ट्र कुछ मायनों में हाशिए पर महसूस करते हैं। जैसा कि माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के राष्ट्रपति डेविड पैनुएलो ने टिप्पणी की, "हमने जो देखा है वह है कि दक्षिण प्रशांत, उत्तरी प्रशांत को तिरस्कार की नज़र से देखता है"(देखें:https://www.abc.net.au/radio-australia/programs/pacificbeat/fsm-pres-covid-pif/13120114)

कई पीआईसी'ज़ के सार्वजनिक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।[37] कई द्वीपों में अब प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने के लिए राजकोषीय स्थिति काफी कम है, और जलवायु अनुकूलन और लचीलापन के वित्तपोषण के लिए नए ऋण लेने के लिए भी कम अवसर हैं। इन निवेशों को स्थायी रूप से वित्तपोषित करने के तरीके खोजना पीआईसी'ज़ के लिए एक उच्च प्राथमिकता है।[38]

पीआईसी'ज़: अल्पावधि आउटपुट हानि
(जीडीपी में औसत वास्तविक वृद्धि)

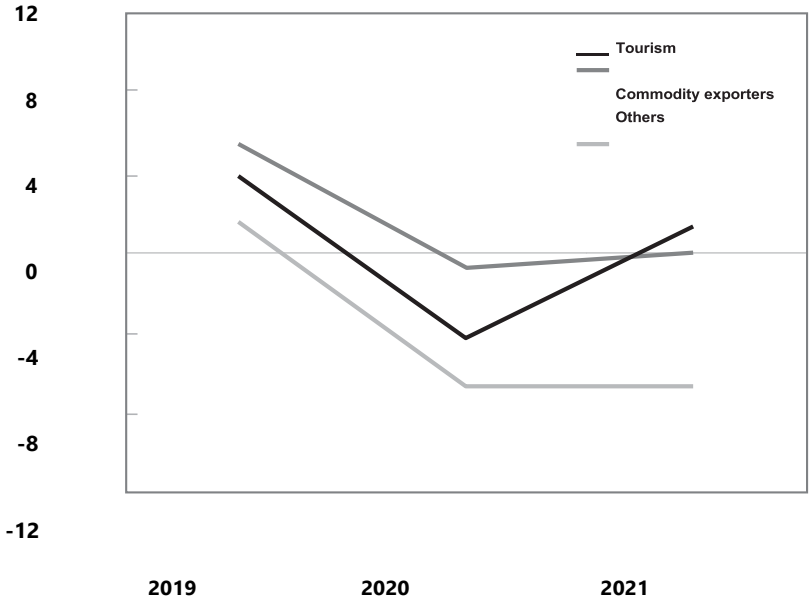

नोट: पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में फ़िज़ी पलाऊ, समोआ, टोंगा, और वानुअतु कमोडिटी अर्थव्यवस्थाओं में पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप शामिल हैं; और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू और तुवालु शामिल हैं स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और आईएमएफ स्टाफ गणना

चित्र: 3

इसलिए, इस खंड में उल्लिखित चीन के आर्थिक और कूटनीतिक पदचिह्नों को मजबूत करने के आलोक में क्षेत्रीय भू-राजनीति में बदलते रुझानों के अलावा पीआईसी'ज़ के लिए चिंता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

3. दक्षिण प्रशांत में चीन का ज़ोर: हालिया रुझान

हाल के वर्षों में प्रशांत आइलैंड्स क्षेत्र में विकसित होने वाला प्रमुख भू-राजनीतिक परिवर्तन, चीन का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में धीरे-धीरे उभरना है। वर्तमान में, किरिबाती और सोलोमन आइलैंड्स द्वारा ताइवान के प्रति निष्ठा के हाल के अचानक बदलाव के बाद, चौदह पीआईसी'ज़ में से दस के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं।

अधिकांश पीआईसी'ज़ में, सहायता नैरेटिव ने मुख्य रूप से बड़े देशों के साथ उनके संबंधों को निर्धारित किया है। दक्षिण प्रशांत दुनिया के सबसे अधिक सहायता-निर्भर क्षेत्रों में से एक है।

हालांकि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा सहायता और विकास भागीदार बना हुआ है, तथापि पिछले एक दशक में चीन धीरे-धीरे पीआईसी'ज़ के सर्वोच्च दानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है, इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पारंपरिक प्रमुख दाताओं के रूप में स्थिति को चुनौती दे रहा है (तालिका 3 देखें)। चीन ने 2009-2021 तक पीआईसी'ज़ को रियायती ऋण सहित लगभग US$ 2.11 बिलियन की सहायता प्रदान की है।[39] चीन पीआईएफ़ सदस्य देशों (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। चीन अब इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर इस क्षेत्र को कुल सहायता का लगभग 55 प्रतिशत योगदान देते हैं।[40]

2009 से 2021 तक प्रशांत क्षेत्र को कुल सहायता (US$ बिलियन में)
तालिका सं.: 3

ऑस्ट्रेलिया	10.88
न्यूज़ीलैंड	2.16
चीन	2.11

संयुक्त राज्य अमेरिका	1.85
एशियाई विकास बैंक	1.73
जापान	1.87
यूरोपीय संघ	1.43
विश्व बैंक	1.21

इनमें से अधिकांश छोटे द्वीपीय देश ऋण संकट के उच्च जोखिम में बने हुए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उन पर चीन के कुल बकाया विदेशी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा शेष है। पापुआ न्यू गिनी पर चीन का सबसे बड़ा ऋण है, लगभग US$590 मिलियन, जो इसके कुल विदेशी ऋण का लगभग एक-चौथाई है।[41]

चित्र सं. 4

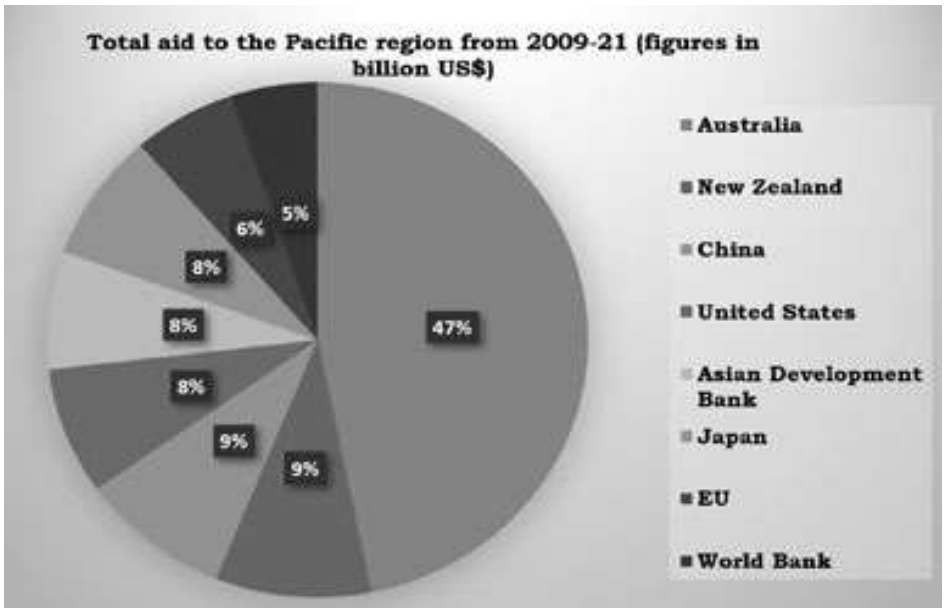

डेटा स्रोत: लोवी इंस्टीट्यूट, पैसिफ़िक एड मैप

चित्र सं. 5

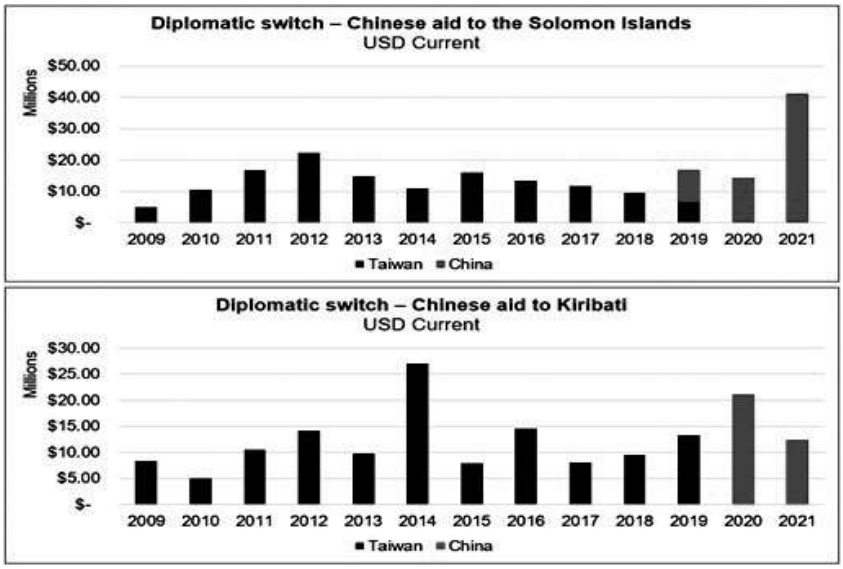

स्रोत: A Dayant, https://twitter.com/AlexandreDayant, https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के अनुमान के अनुसार, जून 2020 के अंत तक, टोंगा पर कुल सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत (पीपीजी) US$184 मिलियन का बाहरी ऋण है, जो कि जीडीपी का लगभग 36 प्रतिशत है। टोंगा के ऋण दायित्व काफी हद तक बाहरी हैं, और इसके कुल सार्वजनिक ऋण का आधा हिस्सा चीन का है, वित्त वर्ष 2024 के बाद से कर्ज अदायगी में तेज़ी से वृद्धि हुई है। टोंगा ने वित्त वर्ष 2019 में चीन के एक्जिम बैंक को पुनर्भुगतान शुरू किया, जिसमें वित्त वर्ष 2024 से बड़े भुगतान देय हैं।[42] 2006 में दंगों के बाद अपने केंद्रीय व्यवसाय जिले के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए ऋण पर, 2024 में चीन को कर्ज का भुगतान बढ़ जाएगा।[43]

चित्र सं.: 6

टोंगा का सार्वजनिक ऋण दायित्व

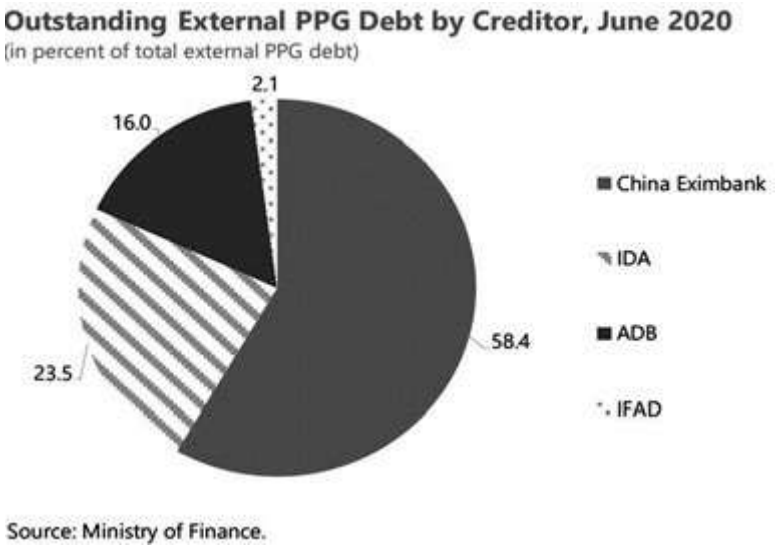

वानुअतु के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण 2014 में 26.1 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में सकल घरेलू उत्पाद का 52.4 प्रतिशत हो गया।

इनमें से अधिकांश छोटे द्वीपीय देश ऋण संकट के उच्च जोखिम में बने हुए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उन पर चीन के कुल बकाया विदेशी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा शेष है।

यह मुख्य रूप से, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और चीन के निर्यात-आयात बैंक (चाइना एक्ज़िम बैंक) सहित, द्विपक्षीय भागीदारों द्वारा समर्थित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए नए संवितरण के

कारण हुआ। वानुअतु पर बाहरी ऋण के रूप में US$152 मिलियन बकाया है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 32.3 प्रतिशत है।[44]

बहुपक्षीय स्तर पर, चीन प्रशांत द्वीप क्षेत्रीय संगठनों में गहराई से शामिल है, हालांकि यह केवल एक डायलॉग पार्टनर है। 25 अगस्त, 2022 को, पीआईएफ़ ने घोषणा की कि चीन की सरकार ने चीन-प्रशांत द्वीप मंच सहयोग कोष के तहत पीआईएफ़ सचिवालय को US$1.08 मिलियन की वार्षिक निधि का योगदान दिया है।[5] पीआईएफ़ के महासचिव हेनरी पुना ने कहा कि "आज चीन की फंडिंग का योगदान का 80 प्रतिशत से अधिक प्रशांत व्यापार और निवेश चीन कार्यालय को निजी क्षेत्र के साथ काम करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने, खरीदारों के साथ निर्यात अवसरों को सुविधाजनक बनाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करेगा"।[45]

इन देशों को अब तक बीजिंग से जो बड़ी मात्रा में सहायता मिली है, वह कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए है। अन्य छोटे देशों को भी चीन की सहायता और समर्थन के रुझान को देखते हुए, बड़े पैमाने पर ऋण-आधारित बुनियादी ढाँचे के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह इन द्वीप राष्ट्रों को ऋण-संजाल के जोखिम में डाल रहा है।

3.1 क्षेत्र में चीन द्वारा वित्तपोषित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

चीन अपने बीआरआई के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण प्रशांत सहित इंडो-पेसिफ़िक उपक्षेत्रों के साथ संपर्क मजबूत कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती रुचि का एक महत्वपूर्ण आयाम इन द्वीपीय देशों की भूमिका के संदर्भ में रहा है जोकि चीन के बीआरआई में, "स्थित हैं, क्योंकि ये बीआरआई के दक्षिण की ओर विस्तार में हैं।[46] क्षेत्र को बीजिंग की सहायता और समर्थन ज्यादातर ऋण आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में आई है। प्रशांत आइलैंड्स चीन की पहल में प्रमुखता से शामिल हैं क्योंकि "21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो एक मार्ग में दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर

[5] चीन 1990 से पैसिफ़िक आइलैंड्स फ़ोरम का फ़ोरम डायलॉग पार्टनर है। व्यापार, निवेश, पर्यटन और कर्मचारियों के आदान-प्रदान में द्विपक्षीय सहयोग का समर्थन करने के लिए 2000 में चीन-प्रशांत द्वीप मंच सहयोग कोष की स्थापना की गई थी।

के माध्यम से चीन के तटीय बंदरगाहों को यूरोप से जोड़ता है, और दूसरे में दक्षिण चीन सागर को दक्षिण प्रशांत से जोड़ता है।"[47] निवेश करने की बीजिंग की इच्छा, क्षेत्र के द्वीप राष्ट्रों के लिए एक विकल्प के रूप में आई थी, जिन्हें इस तरह की सहायता की आवश्यकता थी।

फ्रैंक बैनिमारामा, फ़िज़ी के प्रधान मंत्री, बीजिंग में मई 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बेल्ट एंड रोड फ़ोरम में उपस्थित राष्ट्रों के प्रमुखों में से एक थे। चीन ने अब उन सभी दस देशों के साथ बीआरआई पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं और उन्होंने पीएनजी और वानुअतु के साथ एक बीआरआई सहयोग योजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं।[48] ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय पीएनजी के प्रधान मंत्री पीटर ओ 'नील ने टिप्पणी की थी कि "बीआरआई एक बड़ी पहल है क्योंकि बाज़ार खुल गया है और पूंजी और बुनियादी ढांचा निर्माण क्षमता तक पहुंच हो गई है जिसे अब हम चीन के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।"[49]

हाल ही में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के साथ, द्वीप राष्ट्रों ने सहायता के लिए अपने उत्तर की ओर अधिक देखना शुरू कर दिया है।

इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती रुचि का एक महत्वपूर्ण आयाम इन द्वीपीय देशों की चीन की बीआरआई में भूमिका के संदर्भ में रहा है। क्षेत्र को बीजिंग की सहायता और समर्थन ज्यादातर ऋण आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में आई है।

चीन पीएनजी के मानुस द्वीप में एक बहुउद्देश्यीय बंदरगाह बनाने, पीएनजी में कुमुल घरेलू पनडुब्बी केबल परियोजना, US$ 24.53 मिलियन की लागत से पीएनजी में पॉवर ग्रिड विकास परियोजना जैसी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है।

पीएनजी में स्थित 2100 वर्ग किमी के मानुस द्वीप में चीन का निवेश द्वीप की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण है। "मुख्य भूमि पीएनजी के उत्तर में मानुस की कमांडिंग स्थिति से चीन पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट और न्यूजीलैंड की ओर जाने वाले एसएलओसी को विनियमित कर सकेगा।"[50] ऐतिहासिक रूप से, मानुस द्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना था, जिसका व्यापक रूप से

चित्र सं.: 7
रणनीतिक रूप से स्थित मानुस इस्लान

प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों के अभियान के लिए उपयोग किया जाता था। आइलैंड हाउस लोमब्रम नेवल बेस वर्तमान में पीएनजी रक्षा बल द्वारा उपयोग किया जाता है। लोमब्रम नौसेना बेस के निकटतम हवाई क्षेत्र मोमोटे हवाई अड्डे पर एक विस्तार और उन्नयन परियोजना पर उल्लेखनीय प्रगति की जा रही है, जिसमें निर्माण ठेकेदार एक चीनी कंपनी है।[51] पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संचालन की निगरानी और सहायता के लिए मानुस द्वीप पर चीनी सुविधाओं का बीजिंग द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।[52]

चीन ने वानुअतु में तन्ना और मालेकुला तथा लुगानविले व्हार्फ़ पुनर्विकास में सड़क उन्नयन का भी वित्तपोषण किया है, जिसे चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा वित्त पोषित किया गया है।[53] लुगानविले व्हार्फ के पुनर्विकास पर चीन ने US$80.56 मिलियन खर्च किए जिससे वानुअतु में चीनी नौसेना सेना की संस्थापन की आशंका बढ़ गई।[54] ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया कि चीनी और वानुअतु के अधिकारियों ने लुगानविले व्हार्फ पर एक संभावित चीनी सैन्य अड्डे के संबंध में प्रारंभिक वार्ता की, जिसे चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।[55] इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, पीएनजी और सोलोमन आइलैंड्सको जोड़ने के लिए हाई-स्पीड अंडरसीट कम्युनिकेशन केबल के निर्माण में चीन का स्थान लेने के लिए तत्पर था। अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, जिन्हें चीन ने वानुअतु में वित्त पोषित किया है, इसकी संसद, एक राजमार्ग, एक टूना प्रसंस्करण संयंत्र और एक 1,000 क्षमता वाला सम्मेलन केंद्र शामिल है।[56]

फ़िज़ी में, चीन पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया के बाद US$274.98 मिलियन देकर दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता रहा है। चीन ने US$98.82 मिलियन की लागत से नबौवालु ड्रेकेटी में सड़क उन्नयन परियोजना को वित्तपोषित किया है।

कुक आइलैंड्स में, चीन ने पिछले एक दशक में US$45.15 मिलियन की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। प्रमुख परियोजनाएं अर्बन कन्स्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और

चाइना सिविल इंजीनियरिंग कोऑपरेशन द्वारा शुरू की गईं।[57]

समोआ में, पिछले एक दशक में चीन US$313.17 मिलियन के साथ सबसे अधिक दानकर्ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया US$311.46 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। चीन द्वारा वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं में

फलेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, एक कन्वेंशन सेंटर, नेशनल मेडिकल सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय का मुख्यालय और अन्य सरकारी कार्यालय शामिल हैं।

2019 के बाद से सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती में चीन का निवेश काफी बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने बीजिंग के प्रति निष्ठा बदल ली है। किरिबाती बीजिंग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चीन का उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थित है जो चीन की एकमात्र अपतटीय उपग्रह सुविधा है।[58] सोलोमन द्वीप में, यह पता लगा कि चाइनीज सैम एंटरप्राइज ग्रुप ने शुरू में 75 वर्षों के लिए सोलोमन और उसके आसपास के पूरे तुलागी द्वीप के लिए विकास अधिकार हासिल करते हुए एक समझौता किया था, जिसे आगे नवीकृत किया जा सकता है। हालांकि, बाद में इस डील को खारिज कर दिया गया था। द्वीप रणनीतिक रूप से स्थित है और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में मित्र देशों की सेना के लिए एक गहरे पानी के बंदरगाह के रूप में काम किया था।[59] अब दोनों देशों के बीच कूटनीति की स्थापना के साथ सोलोमन आइलैंड्स देश में चीनी निवेश की उम्मीद कर रहा है। दिसंबर 2020 में, सरकार की नीतियों द्वारा भड़काने, विशेष रूप से इसके बीजिंग समर्थक रवैये के कारण, देश ने हिंसक विरोध देखा। सोलोमन आइलैंड्स के प्रधान मंत्री मनासी सोगावारे को संसद में अविश्वास मत का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने चीन के साथ संबंधों को बदलने के अपने फैसले का बचाव किया और साथ ही द्विपक्षीय भागीदारों- अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड- और बाकी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखे।

उन्होंने कहा कि "चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हमें अपनी विकास आवश्यकताओं और चुनौतियों से जुड़ने और उनका समाधान करने का अवसर प्रदान करता है"।[60] मई 2022 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान, दोनों देश बीआरआई के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण पर सहमत हुए।

रणनीतिक महत्व के द्वीपों में इस तरह की बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोस में चीन की मजबूत पैठ के अंतर्गत भय पैदा किया है। इसने ग्वादर, हंबनटोटा के रणनीतिक बंदरगाहों और जिबूती में सैन्य अड्डे के हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अतीत के उदाहरणों पर विचार करते हुए, इस क्षेत्र में चीन की सक्रिय उपस्थिति की भविष्य की संभावनाओं के प्रति आशंका जताई है। कर्ज के संजाल से परे, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता है वह है "अल्पकालिक मध्यम अवधि की आर्थिक समस्याएं जो बीआरआई मेजबान देशों के लिए पैदा कर सकती है, जैसे कि विकट राजकोषीय मुद्दे, भुगतान संतुलन संकट, और विदेशी भंडार में नाटकीय गिरावट"।[61]

इन बुनियादी ढांचे के विकास को संचालित करने वाले अधिकांश चीनी उद्यमों के चीनी अधिकारियों के साथ संबंध हैं। चीन एक विशिष्ट "सैन्य-नागरिक संलयन" (एमसीएफ़) रणनीति अपनाता है। एमसीएफ़ चीन के नागरिक अनुसंधान और वाणिज्यिक क्षेत्रों, और उसके सैन्य और रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बाधाओं का उन्मूलन है।[62] चीनी समाज के "वाणिज्यिक" और "नागरिक" हिस्सों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का समर्थन किए जाने की उम्मीद है।[63]

चीन इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए अपनी वित्तीय ताकत और आर्थिक कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे संकेत हैं कि बीजिंग वाणिज्यिक उद्देश्यों के अलावा अपनी सैन्य और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए बंदरगाह निवेश का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

चीन ने धीरे-धीरे एक आधुनिक और उन्नत नौसैनिक बल विकसित किया है ताकि वह अपने तटों से परे शक्ति प्रदर्शित कर सके। पीएलए नौसेना बल प्रक्षेपण क्षमताओं से अच्छी तरह सुसज्जित है जैसे विमान वाहक, हमला करने वाली और पारंपरिक पनडुब्बियां, लंबी दूरी के टोही विमान, और बड़ी संख्या में समुद्र में जाने वाले

प्लेटफार्म जिनमें पर्याप्त सी-लिफ़्ट क्षमताएं भी हैं।[64] अब इसके बीआरआई के साथ, चीन इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए अपनी वित्तीय ताकत और आर्थिक कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे संकेत हैं कि बीजिंग वाणिज्यिक उद्देश्यों के अलावा अपनी सैन्य और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए बंदरगाह निवेश का उपयोग करने की योजना बना रहा है। जैसा कि अफ्रीका में कई बंदरगाहों के मामले में चीन की सहायता से किया जा रहा है, चीनी नौसैनिक जहाजों द्वारा भी दौरा किया जाता है या असैन्य सैन्य बंदरगाहों का उपयोग किया जाता है।[65] इन बुनियादी ढांचे के विकास को चलाने वाले अधिकांश चीनी उद्यमों के चीनी अधिकारियों के साथ संबंध हैं। वास्तविक या घोषित मकसद के बावजूद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परियोजनाओं का दायरा और पैमाना चीन को क्षेत्र में शक्तिशाली दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव प्रदान कर सकता है, और इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित होता है।

बीजिंग ने इस क्षेत्र में खानों, पनबिजली परियोजनाओं और रियल एस्टेट में व्यापक निवेश किया है। इसके अलावा, चीन ने क्षेत्रों की मत्स्य पालन, जलीय कृषि[66]और द्वीपों के विस्तृत ईईजेड में अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भी रुचि दिखाई है। बीजिंग की दिलचस्पी उच्च मूल्य की इमारती लकड़ी में भी है, जोकि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन क्षेत्र में निकालना मुश्किल है। 8 दिसंबर 2021 को, पहला 'चाइना पैसिफ़िक आईलैंड कंट्रीज (पीआईसी'ज़) फ़ोरम ऑन फिशरी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट' ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वांगझू में आयोजित किया गया था। मंच ने अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने, जलीय कृषि प्रौद्योगिकी, मत्स्य सुविधाओं और उपकरण, और जलीय उत्पाद प्रसंस्करण और

चाइना-पीआईसी'ज़ आधुनिक मत्स्य सहयोग और विनिमय के लिए एक केंद्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मत्स्य सहयोग और विकास पर पहले चीन-प्रशांत द्वीप देश फ़ोरम की एक ' ग्वांगझू कंसेंसस' मंच पर अपनाई गई।[67] अन्ततोगत्वा सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चीनी प्रभाव के बारे में पारंपरिक क्षेत्रीय खिलाड़ियों की आशंकाएं भी हैं।

3.2 हाल की उच्च स्तरीय बातचीत

हाल के वर्षों में, चीन और पीआईसी'ज़ के बीच राजनयिक बातचीत भी अक्सर उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ होती रही है। 2014 में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ़िज़ी की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान 22 नवंबर 2014 को चीन के साथ राजनयिक संबंधों वाले पीआईसी'ज़ के नेताओं के साथ पहली बैठक हुई। यह तब की बात है जब भारत ने 19 नवंबर 2014 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ़िज़ी यात्रा के दौरान बहुराष्ट्रीय 'फ़ोरम फ़ॉर इंडिया-पैसिफ़िक आईलैंड कोऑपरेशन' (एफआईपीआईसी) का शुभारम्भ किया था। नवंबर 2018 में एक बार फिर, जब पीएनजी ने शिखर सम्मेलन से पहले पोर्ट मोरेस्बी में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विशेष रूप से बीआरआई पर सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आठ छोटे द्वीप देशों के नेताओं, जिनके चीन के साथ राजनयिक संबंध थे, के साथ एक विशेष मंच आयोजित किया। इनमें कुक आइलैंड्स, फ़िज़ी, माइक्रोनेशिया, नीयू, समोआ, टोंगा, वानुअतु और पापुआ न्यू गिनी के नेता शामिल थे। बैठक में राष्ट्रपति शी ने अन्य बातों के अलावा यह प्रस्ताव भी रखा कि चीन 2019 की दूसरी छमाही में द्वीप राष्ट्रों के साथ संयुक्त 'चाइना-पैसिफ़िक आईलैंड कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन फ़ोरम' की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

चीन भी दो बार विदेश मंत्री के स्तर पर ऐसी बैठकें कर चुका है। सबसे हाल की बैठक मई 2022 में वांग यी की प्रशांत आइलैंड्स की यात्रा के दौरान आयोजित की गई थी। बैठक में, वांग यी ने सबसे पहले बैठक में राष्ट्रपति

शी जिनपिंग की लिखित टिप्पणी पढ़ी, जिसमें कहा गया था, "हाल के वर्षों में, चीन-पीआईसी'ज़ की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने जिसमें आपसी सम्मान और सामान्य विकास शामिल है, लगातार प्रगति की है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग, पारस्परिक लाभ और जीत-जीत का एक अनुकरणीय मॉडल स्थापित करते हुए फलदायी परिणाम प्राप्त किए हैं.....चीन सभी देशों की समानता के लिए प्रतिबद्ध है।[68] वांग यी की यात्रा दिलचस्प रूप से चीन-सोलोमन आइलैंड्स सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद और 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड लीडर की सफल व्यक्तिगत बैठक के ठीक बाद हुई जहां अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफ़िक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बाद में फ़िज़ी भी शामिल हो गया। वांग यी ने फ़िज़ी में पीआईएफ़ के महासचिव हेनरी पुना से भी मुलाकात की। व्यापार और सुरक्षा पर क्षेत्र के दस देशों के साथ एक क्षेत्र-व्यापी समझौते पर हस्ताक्षर करने के चीन के इरादे के बारे में मीडिया रिपोर्टें आईं थीं। हालाँकि, प्रस्ताव को वास्तविक रूप नहीं दिया गया क्योंकि कुछ प्रशांत देशों ने प्रस्ताव के ख़ास तत्वों के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

वांग यी की यात्रा से पहले, चीनी विदेश मंत्रालय ने 24 मई 2022 को 'कॉओपरेशन बिटविन चाइना एंड पेसिफ़िक आईलैण्ड कंट्रीज़: फैक्ट शीट' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। दस्तावेज़ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चीन और पीआईसी'ज़ के बीच लंबे समय तक चलने वाला मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान है, जिसे 2014 में पीआईसी'ज़ के साथ राष्ट्रपति शी की पहली बैठक के दौरान 'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में मान्यता दी गई थी, और इसे 2018 में दूसरी बैठक में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया गया था। रिपोर्ट ने पीआईसी को बीजिंग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापार भागीदारों के रूप में मान्यता दी,

और क्षेत्र में द्वीपीय राज्यों के साथ चीन के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और विकास सहयोग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।[69]

इसलिए, बीजिंग क्षेत्र में अपनी राजनयिक और आर्थिक उपस्थिति और पीआईसी के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास कर रहा है। लगातार उच्च स्तरीय बातचीत से पता चलता है कि यह क्षेत्र एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के चीन के रणनीतिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनता जा रहा है।

3.3 सुरक्षा सहयोग के लिए चीन-सोलोमन आइलैंड्स रूपरेखा समझौता: एक विश्लेषण

ताजा घटनाक्रम जिसने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है वह है सोलोमन द्वीप और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर। 19 अप्रैल 2022 को पुष्टि किए गए समझौते ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रशांत देशों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। 19 अप्रैल 2022 को पुष्टि किए गए समझौते ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य प्रशांत देशों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। यह डील प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग का पहला ज्ञात द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता है। फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होता है जो पांच वर्ष की अनुक्रमिक अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगा।[70]

समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से किए गए हैं। डील में इसे अपरिहार्य बनाया गया है कि"चीन अपनी जरूरतों के अनुसार और सोलोमन आइलैंड्स की सहमति से, जहाज़ों का दौरा करवा सकता है, रसद की पुनःपूर्ति कर सकता है, और स्टॉपओवर कर सकता है और सोलोमन आइलैंड्स में आवागमन कर सकता है सोलोमन आइलैंड्स में चीनी कर्मियों और प्रमुख परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए चीन की संबंधित ताकतों का उपयोग किया जा सकता है।[71]

इसका भी उल्लेख किया गया है कि, " सोलोमन आइलैंड्स, अपनी जरूरत के अनुसार, दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और जीवन और संपत्ति की रक्षा करने, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए और आपदा प्रतिक्रिया को अंजाम देने के लिए और अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए सोलोमन आइलैंड्स में पुलिस, सैन्य कर्मियों, अन्य कानून प्रवर्तन और सशस्त्र बलों को भेजने के लिए चीन से अनुरोध कर सकता है।"[72] सोलोमन आइलैंड्स आंतरिक सुरक्षा स्थिति के विवरण और आवश्यक सहायता के विवरण के साथ, उचित राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीन को लिखित रूप में ऐसा अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद 5 के अधीन 'गोपनीयता' पर समझौते का एक और खंड, जिसने क्षेत्रीय देशों की चिंताओं को उठाया है, डील की प्रकृति से संबंधित है, जैसा कि सौदे की आवश्यकता है कि "दो पक्षों की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को सहयोग की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है"।

सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने समझौते का बचाव किया है क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स के विदेश मामलों के स्थायी सचिव कॉलिन बेक ने कहा कि समझौते का "चीन को देश में स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है", बल्कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि डील की अनुचित और अवांछित गहन जांच की गई है। डील को प्रशांत देश में विकास की जरूरतों को पूरा करने और "घरेलू सुरक्षा खतरों" से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की समस्या और पुरानी बेरोजगारी और ऐसे अन्य मुद्दे।[73] उन्होंने यह भी कहा कि अन्य कई गठबंधन भी हैं

सोलोमन आइलैंड्स में विपक्ष ने इस पर चिंता जताई है कि डील चीनी सशस्त्र पुलिस और सैन्य कर्मियों को लोकतांत्रिक असंतोष को कुचलने और आने वाले वर्षों के लिए सत्ता पर काबिज होने में पीएम सोगावारे के लिए सहायक हो सकती है।

फाइव आई एलायंस और सोलोमन आइलैंड्स की तरह प्रशांत क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सुरक्षा संधि है।[6]

देश के भीतर विपक्ष ने इस पर चिंता जताई है कि डील चीनी सशस्त्र पुलिस और सैन्य कर्मियों को लोकतांत्रिक असंतोष को कुचलने और आने वाले वर्षों के लिए सत्ता पर काबिज होने में पीएम सोगावारे के लिए सहायक हो सकती है। विपक्ष ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सोलोमन जैसे नाजुक देश में, चीनी नीतियों और रणनीति से और अस्थिरता पैदा हो सकती है। सोलोमन द्वीप के विपक्षी दल के नेता मैथ्यू वाले ने कहा कि चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का सरकार का निर्णय "राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में" नहीं है।[74]

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश ने नवंबर 2021 में राजधानी होनियारा में सरकार के खिलाफ गर्म राजनीतिक तनाव और हिंसक विरोध देखा था। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक मुद्दों के अलावा,

[6] 14 अगस्त 2017 को, ऑस्ट्रेलियाई और सोलोमन द्वीप के विदेश मंत्रियों द्वारा द्विपक्षीय सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत "ऑस्ट्रेलियाई पुलिस, रक्षा और संबंधित नागरिक कर्मियों को जरूरत पड़ने पर और जहां दोनों देशों की सहमति हो, सोलोमन द्वीप पर तेजी से तैनात करने की अनुमति देती है"। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2021 में संकट के दौरान संधि के तहत अपनी सहायता भेजी है। यह प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की पहली द्विपक्षीय सुरक्षा संधि है और इसने रीजनल असिस्टेंस मिशन टू सोलोमन आइलैंड्स (आरएएमएसआई) संधि का स्थान लिया है। जो सोलोमन द्वीप और प्रशांत क्षेत्र के पंद्रह योगदान देने वाले देशों के बीच एक समझौता था, और 30 जून 2017 को आरएएमएसआई की वापसी पर समाप्त हो गया। देखें: https://www.dfat.gov.au/geo/solomon-islands/Pages/Bilateral-security-treaty इसे भी देखें: प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ संयुक्त मीडिया वक्तव्य, 25 नवंबर 2021, https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/solomon-islands

यह वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति बड़े पैमाने पर असंतोष था, विशेष रूप से इसके बीजिंग समर्थक रुख और चीन के साथ राजनयिक संबंधों के स्थानांतरण ने वर्तमान संकट को हवा दी। सोलोमन आइलैंड्स का भी अंतर-द्वीप तनाव का इतिहास रहा है। नवंबर 2021 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत मलाइता प्रांत से थे, जहां प्रांतीय सरकार के वर्षों से केंद्र सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं।[75] वर्तमान प्रधानमंत्री मनश्शे सोगावारे देश की राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। तत्कालीन सरकार के खिलाफ तख्तापलट के बाद उन्हें पहली बार 2000 में प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था।[76] वर्तमान में, वह अपनी सेवा के चौथे कार्यकाल में सेवाएं दे रहे है। गुप्त डील अब और घरेलू तनाव पैदा कर सकती है।

इस डील ने निश्चित रूप से क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति के डर से अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। डील पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के अधिकारियों ने डील के प्रस्तावित ढांचे पर चिंता व्यक्त करते हुए, और "मुक्त और खुले इंडो-पेसिफ़िक के लिए गंभीर जोखिम बताते हुए" प्रशांत आइलैंड्स में विकास पर चर्चा करने के लिए होनोलूलू में एक बैठक बुलाई थी।[77]

डील पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद, 22 अप्रैल 2022 को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडो-पैसिफ़िक के कोऑर्डिनेटर, कर्ट कैंपबेल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने प्रशांत क्षेत्र का दौरा किया और सोलोमन आइलैंड्स का भी दौरा किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने "उद्देश्य, दायरे और समझौते की पारदर्शिता के संबंध में चिंता के स्पष्ट क्षेत्रों" को रेखांकित किया,[78] और यह भी कहा कि "वास्तव में स्थायी सैन्य उपस्थिति, शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं, या एक सैन्य प्रतिष्ठान के किसी भी प्रयास के मामले में, अमेरिका तदनुसार प्रतिक्रिया करेगा।"[79] क्षेत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने

सहयोगियों के साथ सहयोग करने और क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करने की इच्छा पर भी प्रकाश डाला।

क्षेत्रीय देशों को लगता है कि यह डील क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दोनों ने समझौते को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सैन्यीकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है।

यह डील ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ इसकी आत्म-धारणा के लिए दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में चिंता का कारण है। ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन विदेश मंत्री मारिस पायने ने "पारदर्शिता की कमी" के बारे में चिंता व्यक्त की थी जैसा कि उन्होंने कहा, "इस पर खुले और पारदर्शी तरीके से सहमति नहीं दी गई है, उदाहरण के लिए पूरे क्षेत्र में इस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है।" समझौते पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने होनियारा के शीर्ष अधिकारियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रशांत मंत्री जेड सेसेल्जा को सोलोमन आइलैंड्स भेजा।[80] तत्कालीन पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इस सौदे पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की कि'यह ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रीय सरकारों के लिए एक साझा चिंता है। चीनी सैन्य नौसैनिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और उसके सहयोगियों के लिए एक 'लाल रेखा' होगी।[81] ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो उस समय विपक्ष में थी, ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति की सबसे बड़ी भूल मानते हुए, मुद्दों से निपटने में सरकार की आलोचना की।[82] चीन-सोलोमन डील के आलोक में ऑस्ट्रेलिया ने अपने क्षेत्र के करीब एक संभावित सैन्य अड्डे पर चिंता जताई थी। जुलाई 2022 में फ़िज़ी की अपनी यात्रा के दौरान, 51 वें पैसिफ़िक आइलैंड फ़ोरम (पीआईएफ़) लीडर्स समिट के लिए, वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीस ने पीआईएफ़ बैठक में भाग लिया, और शिखर सम्मेलन के मौके पर कुछ द्वीप देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने सोलोमन आइलैंड्स के पीएम मनश्शे सोगावारे से भी मुलाकात की। बैठक के बाद बताया जाता है कि, प्रधान मंत्री अल्बानीस ने कहा कि "हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है, हम सोलोमन में किसी भी स्थायी

उपस्थिति के बारे में चिंतित होंगे, निश्चित रूप से, ऑस्ट्रेलिया के इतने क़रीब"।[83] उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि बैठक उपयोगी थी और उन्हें "बहुत विश्वास" था कि चीन को सोलोमन आइलैंड्स में सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।[84]

इसी तरह, न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डर्न, जब सिंगापुर में, महामारी के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर गई थीं, ने मीडिया को बताया कि "इस समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं ... हमें स्पष्ट रेखाएँ खींचनी चाहिए जहाँ हमारे पास चिंता के क्षेत्र हैं और हमारे क्षेत्र का सैन्यीकरण एक स्पष्ट रेखा है"। उहोंने कहा कि 'डील पर एक क्षेत्रीय आधार पर व्यापक चर्चा होने की जरूरत है'।[85] 51वीं पीआईएफ़ शिखर बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम अर्डर्न ने एक बार फिर से यह बात दोहराई कि "क्षेत्र के सैन्यीकरण पर हमारा बहुत मजबूत दृष्टिकोण है"।[86] इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कि कैसे एक देश द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता पूरे प्रशांत परिवार को प्रभावित करता है, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें स्थापित करने की क्या ज़रूरत है - एक मंच के रूप में और एक परिवार के रूप में - क्या अपेक्षा है जब हमारे पास नए रिश्ते बनाने का प्रयास है जो इस क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता है? क्या सूचना... क्या इस क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है? और यह उम्मीद करना उचित है कि एक परिवार के रूप में हम सबसे पहले उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और व्यवस्था करते हैं?[87]

जैसा कि हाल ही में मीडिया में बताया गया है, सोलोमन द्वीप ने यूएस कोस्टगार्ड कटर, यूएससीजीसी ओलिवर हेनरी को होनियारा में "रूटीन लॉजिस्टिक्स पोर्ट कॉल" करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है - जो वाशिंगटन और प्रशांत राष्ट्र के बीच बिगड़ते संबंधों का एक और संकेत है। सोलोमन सरकार ने "जहाज में ईंधन भरने और प्रावधान के लिए राजनयिक मंजूरी हेतु अमेरिकी सरकार के अनुरोध" का जवाब नहीं दिया।[88]

सोलोमन द्वीप द्विपक्षीय डील के साथ, स्पष्ट रूप से बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों को पाने की कोशिश कर रहा है। इस समझौते के परिणामस्वरूप क्षेत्र में चीन के रणनीतिक लक्ष्यों के बारे में क्षेत्रीय देशों के बीच आशंकाएं और बढ़ गई हैं।

4. चेंजिंग पॉवर डायनामिक्स: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक निहितार्थ

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक वातावरण इस पेपर में पहले चर्चा की गई कई महत्वपूर्ण हालिया घटनाओं के साथ तेजी से अस्थायी दिख रहा है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम ऑस्ट्रेलिया के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय बन गए हैं, जो लंबे समय से इस क्षेत्र को अपना बैकयार्ड मानता रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में दिखने की कोशिश करता है और द्वीप महाद्वीप की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक बड़ा बेड़ा तैयार रखता है।[89]

इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के विरुद्ध एक तरह से पुश-बैक में, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी में मानुस में लोमब्रम नौसैनिक अड्डे का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है। लोम्ब्रम और में व्हार्फ सुविधाओं के उन्नयन के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले ही $3.63 मिलियन की प्रतिबद्धता कर चुका है लोम्ब्रम और पीएनजी में रक्षा परियोजनाओं पर कुल $29 मिलियन की घोषणा की है। यह कदम चीन द्वारा मानुस को एक वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में विकसित करने की पेशकश के बाद कथित तौर पर पीएनजी से संपर्क करने के बाद आया है।[90] एपीईसी शिखर सम्मेलन के लिए 2018 में पीएनजी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा के दौरान, तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस ने कहा था, "संयुक्त राज्य अमेरिका पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ मानुस द्वीप पर लोमब्रम नौसेना बेस में उनकी संयुक्त पहल पर भागीदार होगा। हम इन देशों के साथ प्रशांत आइलैंड्सके संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा, "अस्थिर और खराब-गुणवत्ता वाली परियोजनाओं का समर्थन करने वाले बुनियादी ढाँचे के ऋण की शर्तें अपारदर्शी हैं और ऐसे तार जुड़े हुए हैं और चौंका देने वाले ऋण की ओर ले जाते हैं।[91]

वानुअतु में संभावित चीनी आधार के बारे में हाल की मीडिया रिपोर्टों से ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से चिंतित था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया, कि चीनी और वानुअतु के अधिकारियों ने चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा वित्त पोषित लुगानविले व्हार्फ़ पर एक संभावित चीनी सैन्य अड्डे के संबंध में प्रारंभिक वार्ता की।[92] हालाँकि, चीनी और वानुअतु दोनों सरकारों ने ऐसी किसी भी वार्ता से इनकार किया। वानुअतु के विदेश मंत्री राल्फ रेगनवानु ने स्पष्ट किया कि "वानुअतु सरकार में किसी ने वानुअतु में किसी भी प्रकार के चीनी सैन्य अड्डे के बारे में कभी भी बात नहीं की है"।[93] हालाँकि, पूरे प्रकरण ने ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक दायरे में चिंता पैदा कर दी। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत आइलैंड्स में किसी भी विदेशी सैन्य ठिकाने को "बड़ी चिंता" के साथ देखेगा"।[94]

एक अन्य घटना में, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स के लिए हाई-स्पीड अंडरसी टेलीकम्युनिकेशन केबल के निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया चीन की जगह लेने में तत्पर था। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामले और व्यापार विभाग ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि सरकार दूरसंचार कंपनी वोकस के साथ साझेदारी करेगी, जिसे कोरल सी केबल सिस्टम को भौतिक रूप में लगाने के लिए US$136.6 मिलियन मूल्य का ठेका दिया गया था"।[95] मूल रूप से 4,000 किमी लंबे केबल नेटवर्क का निर्माण चीनी दिग्गज कंपनी हुवाई द्वारा किया जाना था, जिसे 2016 में सोलोमन्स द्वारा ठेका दिया था।[96] इन विवादों ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति ऑस्ट्रेलियाई संवेदनशीलता को उजागर किया।

यदि कोई इस क्षेत्र में हाल ही में चीनी और ऑस्ट्रेलियाई सहायता की तुलना करे तो, ऑस्ट्रेलिया से सहायता शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु संबंधी परियोजनाओं, मानवीय सहायता सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में रही है, जबकि बीजिंग की सहायता मुख्य रूप से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के रूप में आई है।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दक्षिण प्रशांत द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्षेत्रीय धारणा में थोड़ी गिरावट आई है। खासकर, फ़िज़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते टूट गए थे, जो 2014 में संसदीय लोकतंत्र में जनता की वापसी के बाद से धीरे-धीरे सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।[97] 2006 में एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बैनिमारामा की आलोचना की थी और फ़िज़ी पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने फ़िज़ी में अंतरिम सरकार के सदस्यों पर लक्षित वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध लगाए। अप्रैल 2009 में फ़िज़ी के संविधान के निरस्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फ़िज़ी के सैन्य शासन की व्यापक अंतरराष्ट्रीय निंदा की।[98] तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री स्टीफन स्मिथ ने कहा कि फ़िजी को हाल के घटनाक्रमों के आलोक में पीआईएफ़ और संभवत: राष्ट्रमंडल से निलंबित किया जा सकता है।[99] फ़िज़ी चीन को पारंपरिक मित्रों के लिए एक आर्थिक, कूटनीतिक और सहायता विकल्प प्रदान करने वाले के रूप में देखता है। सुवा में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चीनी उस समय फ़िज़ी के साथ कठिन परिस्थिति में थे जब देश को 2006 के तख्तापलट प्रतिबंधों के मद्देनजर महसूस किए गए अलगाव का प्रबंधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मित्र की आवश्यकता थी।[100] ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की सीधी आलोचना करते हुए, बनिमारामा ने कहा था कि कि चीन "फ़िज़ी का सच्चा मित्र" रहा है और उसने फ़िज़ी की आंतरिक राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में, इस बात की चिंता है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों में कहीं न कहीं इस

क्षेत्र और इसके लोगों, बड़े पैमाने पर प्रशांत समुदाय के बारे में सांस्कृतिक जागरूकता की कमी है। "ऑस्ट्रेलियाई संवाद में प्रशांत क्षेत्र अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोगों की ओर से प्रशांत आइलैंड्स के बारे में ज्ञान की कमी को चिन्हित करता है।"[101]

अप्रैल 2017 में, फ़िज़ी और पापुआ न्यू गिनी, दो प्रमुख पीआईसी'ज़ ने, यह व्यक्त करते हुए कि क्षेत्रीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड को अधिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापार डील उनके विकासशील उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा, क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशंस प्लस (PACER Plus) पर प्रशांत समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।[102] "PACER Plus प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है और इस क्षेत्र में कई क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों और निवेशकों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है।[103] हालाँकि, कभी-कभी गड़बड़ी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और पीआईसी'ज़ के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ अपने संबंधों को देखने के तरीके में बदलाव आया है। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ 60 वर्षों की अवधि से अधिक का एक मजबूत गठबंधन है। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के बाद के गठबंधन को एशिया-प्रशांत की व्यापक सुरक्षा में वाशिंगटन को शामिल रखने में ऑस्ट्रेलिया की हितों के अनुसार आकार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का भ्रम था कि क्या वह अधिक मुखर चीन के सामने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करे या अधिक स्वतंत्र रक्षा मुद्रा विकसित करे और चीन के साथ तनाव कम करने का प्रयास करे। जैसा कि बेटमैन और गैलडोरिसी लिखते हैं, "ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका और चीन के बीच 'दोनों का समर्थन कर संभावित हार या भूल से अपने को बचाने' में सबसे बड़ा दांव है ...

....दोनों 'गेंदों को बिना उछाले' हवा में रखने के लिए"।[104] इसलिए, 21वीं सदी में कैनबरा के लिए दोनों शक्तियों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन, सबसे कठिन विदेश नीति कार्य रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के 2013 के रक्षा श्वेत पत्र ने तर्क दिया कि,

> *"किसी भी अन्य की तुलना में, अमेरिका और चीन के बीच विश्व और क्षेत्र के दो सबसे शक्तिशाली राज्यों के बीच संबंध, हमारे भविष्य के रणनीतिकवातावरण को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होंगे। अमेरिका निकट भविष्य में हमारे क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली रणनीतिक सक्रियक बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए, सबसे अधिक संभावना वाला भविष्य वह है जिसमें अमेरिका और चीन एक रचनात्मक संबंध बनाए रखने में सक्षम हों...*[105]

इसी तरह, 2016 के रक्षा श्वेत पत्र ने इस बात पर जोर दिया कि "प्रमुख शक्तियाँ अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में अधिक मुखर हो गई हैं और इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रभाव के लिए चीन की सक्रिय खोज सहित, प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तत्काल क्षेत्र में सैन्य ठिकानों की स्थापना क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर कर सकती है। अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कम होने की संभावना नहीं है। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला कि "जबकि चीन अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक वजन से मेल नहीं खा पाएगा, जिसमें उसका सैन्य आधुनिकीकरण भी शामिल है, का अर्थ चीन की नीतियों और कार्यों से है चीन की राष्ट्रीय शक्ति का विकास, अपने सैन्य आधुनिकीकरण सहित, अर्थात् चीन की नीतियां और कार्य, 2035 तक इंडो-पैसिफ़िक की स्थिरता पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा"।[106]

नवीनतम डिफेंस स्ट्रैटेजिक अपडेट 2020 ने पहली बार इस पर प्रकाश डाला कि "रणनीतिक प्रतियोगिता, मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच, इंडो-पैसिफ़िक और हमारे तत्काल क्षेत्र में तेजी से कार्यरत है, यानी दक्षिण पश्चिम प्रशांत में, और यह हमारे क्षेत्र में

रणनीतिक डायनामिक्स का प्रमुख चालक होगा"।[107] जाहिर तौर पर ये नीतिगत दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के तत्काल क्षेत्र में चीन की भूमिका के बारे में धारणा में धीरे-धीरे बदलाव को दर्शाते हैं।

विशेष रूप से महामारी के बाद से ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। 5जी का मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीति में चीनी दखल की कैनबरा की आलोचना, कोविड-19 और उसके बाद दोनों के बीच व्यापार युद्ध सहित, हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधों में कई 'गंभीर बिंदु' उभरे हैं। महामारी के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और चीन वायरस के मुद्दे पर 'वाकयुद्ध' भी शामिल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति की एक स्वतंत्र जांच का आह्वान किया था।[108] बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऑस्ट्रेलिया के कार्यों को 'राजनीति से प्रेरित' बताया और ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का बहिष्कार करने की धमकी दी। व्यापार बाधाओं को कसते हुए, चीन ने चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई बीफ़ आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और ऑस्ट्रेलियाई जौ पर 80 प्रतिशत टैरिफ़ लगा दिया। एक स्पष्ट भय था कि मौजूदा तनाव के बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया को संभवतः हर वर्ष अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। हालाँकि चीन अब भी वस्तुओं और सेवाओं में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दो-तरफा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जो दुनिया के साथ इसके कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई (31 प्रतिशत) हिस्सा है। 2020 में चीन के साथ दो तरफा व्यापार में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कुल $245 बिलियन थी (ऑस्ट्रेलिया का वैश्विक दोतरफा व्यापार इस अवधि के दौरान 13 प्रतिशत घट गया)। चीन द्वारा व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों की कड़ी ने चीन को ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं के निर्यात को भी प्रभावित किया है, जो 2019 की दूसरी छमाही की तुलना में 2020 की दूसरी छमाही में लगभग 7 प्रतिशत कम थी।[109]

जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 21 मई 2022 को संघीय चुनाव के बाद सरकार में बदलाव किया है, लेबर पार्टी के नेता एंथोनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है,

विशेष रूप से महामारी के बाद से ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। 5जी का मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीति में चीनी दखल की कैनबरा की आलोचना, कोविड-19 और उसके बाद दोनों के बीच व्यापार युद्ध सहित, हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधों में कई 'गंभीर बिंदु' उभरे हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई सरकार के अधीन ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध कैसे फलते-फूलते हैं। कार्यभार संभालने के ठीक पांच दिन बाद पेनी वोंग की फ़िज़ी यात्रा दर्शाती है कि नई सरकार के अधीन प्रशांत आइलैंड्सविदेश नीति की प्राथमिकता होगी।

पृष्ठभूमि को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रशांत "स्टेप-अप" नीति के साथ इस क्षेत्र में अपनी बढ़ी हुई भूमिका की घोषणा पहले ही कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की 2017 की विदेश नीति श्वेत पत्र और 2016 की रक्षा श्वेत पत्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि 'पैसिफ़िक स्टेप-अप' ऑस्ट्रेलिया के लिए मौलिक महत्व की नीति है, जो इस क्षेत्र के साथ अपने सतत जुड़ाव पर आधारित है। नीति को अपनी विदेश नीति श्वेत पत्र 2017 में देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रेखांकित किया गया था। जैसा कि तत्कालीन विदेश मंत्री मारिज पायने ने कहा, "प्रशांत क्षेत्र में कदम रखना ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति का विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है"।[110] तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन, विदेश मामलों के मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर पायने द्वारा 8 नवंबर 2018 को जारी एक संयुक्त बयान में, क्षेत्र के साथ सुरक्षा, आर्थिक, कूटनीतिक और लोगों से लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके खोजने पर जोर दिया गया। अन्य पहलों के बीच, इसमें इसमें प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलियाई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सुविधा की स्थापना भी शामिल है, जो प्रशांत देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए A$2 बिलियन (US$1.4 बिलियन) की पहल है।[111]

यह प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सहायता के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने यह भी घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया, पैसिफ़िक आइलैंड्स फ़ोरम के प्रत्येक सदस्य के लिए अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए, प्रशांत क्षेत्र में पाँच नए राजनयिक मिशन स्थापित करेगा। जनवरी 2019 में फ़िज़ी और वानुअतु की अपनी यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त फ़ंडिंग की घोषणा की। उन्होंने PACER Plus (पैसिफ़िक एग्रीमेंट ऑन क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशंस प्लस) के लिए एक नए सिरे से पिच भी बनाई, जो एक प्रशांत मुक्त व्यापार डील है, जिस पर फ़िज़ी और पीएनजी ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अन्य नौ प्रशांत द्वीप देशों के साथ क्षेत्रीय विकास-केंद्रित व्यापार समझौते की पुष्टि की है।[7112]

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग द्वारा 2020 रक्षा रणनीतिक अपडेट में उल्लेख किया गया है कि, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पूर्वोत्तर हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम प्रशांत तक के क्षेत्र सहित हमारे क्षेत्र में रणनीतिक डायनामिक्स की प्रमुख चालक होगी। इसने पड़ोस में पैसिफ़िक स्टेप-अप पॉलिसी जैसी पहल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन को लगातार गहरा करने और इंडो-पैसिफ़िक में क्षेत्रीय जुड़ाव को मजबूत करने की ऑस्ट्रेलियाई सरकार की इच्छा को भी रेखांकित किया।

इसी तरह, न्यूज़ीलैंड के रणनीतिकरक्षा नीति वक्तव्य 2018 ने विकास सहायता और आर्थिक जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। यह उल्लेखनीय है कि चीन का सैन्य आधुनिकीकरण उसकी बढ़ती नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। चीन विकास सहायता के जरिए प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।

[7] यह एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है जिसमें सामान, सेवाएं और निवेश शामिल हैं। PACER Plus पर वार्ता 2009 में शुरू हुई और 20 अप्रैल 2017 को ब्रिस्बेन में संपन्न हुई। देखें:https://dfat.gov.au/trade/ agreements/not-yet-in-force/pacer/Pages/pacific-agreement-on-closer-economic-relations-pacer-plus.aspx

बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगातार व्यवधान बढ़ रहा है क्योंकि "बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े भारी ऋण बोझ के प्रभाव, पहुंच और शासन के लिए संभावित निहितार्थ हैं"।[113] यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच संबंध दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में से एक है।

न्यूजीलैंड ने भी अपनी 2018 की 'पैसिफ़िक रीसेट' नीति के माध्यम से, क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा और निवेश को बढ़ाते हुए, रणनीतिक चुनौतियों और अवसरों पर प्रशांत देशों के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा को दोहराया है। फरवरी 2018 में, न्यूजीलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने "प्रशांत रीसेट" नीति के साथ प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लिए एक ताज़ा दृष्टिकोण की घोषणा की। इस क्षेत्र में न्यूज़ीलैंड की भूमिका बढ़ाने की नीति के हिस्से के रूप में, सरकार ने पीआईसी'ज़ के साथ गहरी और अधिक परिपक्व साझेदारी बनाने के साथ-साथ अपनी राजनयिक और विकासात्मक उपस्थिति बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की।'पैसिफ़िक रीसेट' में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के अन्य प्रमुख साझेदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग भी शामिल है।[114] यह क्षेत्र पहले से ही न्यूज़ीलैंड की सहायता राशि का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त करता है। प्रशांत पड़ोसियों की समृद्धि के प्रति न्यूजीलैंड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए, सरकार ने न्यूजीलैंड सहायता कार्यक्रम के अधीन 2018 के बजट में इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की,[115] जिसमें विविध प्रकार की गतिविधियों के लिए $10 मिलियन के पैसिफ़िक एनेबलिंग फंड की स्थापना शामिल है।[116] न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सामूहिक साइबर लचीलापन बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में परिवर्धित साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक खुले, मुक्त और सुरक्षित इंटरनेट का समर्थन करने के लिए पीआईसी'ज़ के साथ काम करने की संयुक्त प्रतिबद्धता की घोषणा की, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करती हो और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती हो।

न्यूजीलैंड ने अपनी 2018 की 'पैसिफ़िक रीसेट' नीति के माध्यम से, क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा और निवेश को बढ़ाते हुए, रणनीतिक चुनौतियों और अवसरों पर प्रशांत देशों के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा को दोहराया है।

इससे 2022 तक क्षेत्रीय साइबर सहयोग में ऑस्ट्रेलिया का कुल निवेश $38.4 मिलियन हो गया है।[117]

न्यूज़ीलैंड के प्रशांत पड़ोसियों को इसकी आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) फंडिंग का लगभग 60 प्रतिशत[118] प्राप्त होता है, जो कि 2021-22 में NZ$590 मिलियन ($387 मिलियन) की राशि है, यह पिछले वर्ष की NZ$524 मिलियन से अधिक है। न्यूजीलैंड के विदेश मामले और व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 2022 के बजट में "राजकोषीय संकट" का सामना कर रहे प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की सहायता के लिए $75 मिलियन आवंटित किए, जो पिछले दो वर्षों में कोविड-19 आर्थिक सहायता में $325 मिलियन से अधिक है।[119] विभाग पूरे प्रशांत क्षेत्र में विकास सहयोग देने के लिए 30 से अधिक अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।[120]

चीन पर, नवीनतम घटनाक्रमों को देखते हुए, प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने क्षेत्र में एक मुखर चीन से निपटने के लिए बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया और प्रतिक्रियाशील नहीं होना चाहिए। जुलाई 2022 में लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी में अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि "क्षेत्र तेजी से विभाजित और ध्रुवीकृत" नहीं हो जाए, अतः "कूटनीति को सबसे मजबूत उपकरण और सबसे जोरदार कॉल डीस्केलेशन बनना चाहिए"।[121] बीजिंग ने अर्डर्न की टिप्पणियों की "गलत" और "अफसोसजनक" के रूप में आलोचना की।[122] इससे पहले जून 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन में अर्डर्न ने कहा था कि चीन "अधिक मुखर और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानदंडों

को चुनौती देने के लिए अधिक इच्छुक" होता जा रहा है।[123] यह महत्वपूर्ण था क्योंकि न्यूजीलैंड चीन की आलोचना करने वाले ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक सतर्क रहा है और अब तक बहुत मुखर नहीं रहा है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि न्यूजीलैंड का ध्यान उन क्षेत्रों पर बना हुआ है जो पीआईसी'ज़ के लिए प्राथमिक चिंता का विषय हैं, विदेश मंत्री ननैया महुता ने कहा कि "प्रशांत में महाशक्तियों की अधिक रुचि के साथ, प्रशांत क्षेत्र में न्यूज़ीलैंड की विदेश नीति का दृष्टिकोण प्रशांत के लचीलेपन, आर्थिक लचीलेपन, अरक्षितता के स्तर और ऋण संकट पर बना हुआ है।"[124]

मई 2022 में न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न की अमेरिका यात्रा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की प्रशांत आइलैंड्स की यात्रा के साथ हुई। दोनों पक्षों ने व्यक्त किया कि इंडो-पैसिफ़िक में परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है, जहां हाल के दशकों में स्थिरता, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने वाले मूल्य, मानदंड और नियम खतरे में हैं।[125] राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम अर्डर्न के साथ बैठक के दौरान कहा कि "हमें उन प्रशांत द्वीपों में और काम करना है"।[126]

"प्रशांत, इंडो-पैसिफ़िक और विश्व के लिए 21वीं सदी की साझेदारी" शीर्षक वाली बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में, यह नोट किया गया कि "हम प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से चिंतित हैं, जो मौजूदा संस्थानों और व्यवस्थाओं को कमजोर करने की धमकी देती है जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को कम होती है। यह भी नोट किया गया कि "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच सुरक्षा समझौते पर भी चिंता व्यक्त की... विशेष रूप से, एक चिंता जोकि एक राज्य द्वारा प्रशांत क्षेत्र में लगातार सैन्य उपस्थिति की स्थापना जो हमारे मूल्यों या सुरक्षा हितों को साझा नहीं करती है, इस क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन को मौलिक रूप से बदल देगी और हमारे दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय-सुरक्षा चिंताओं को पैदा करेगी।[127]

दोनों पक्षों ने केंद्र में एक मजबूत और एकजुट पीआईएफ़ के साथ प्रशांत आइलैंड्स क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और मत्स्य पालन, समुद्री पर्यावरण की रक्षा, आजीविका, परंपराएं, खाद्य सुरक्षा, और और आर्थिक लाभ, बुनियादी ढांचे पर प्रशांत क्षेत्र में काम का विस्तार सहित, परिवहन और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा; समुद्री सुरक्षा को शामिल करते हुए, अवैध, असूचित, और अनियमित मछली पकड़ने का सामना करने सहित; शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण; COVID-19 महामारी सहायता और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा; और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा; और आर्थिक सुधार सहित और प्रशांत प्राथमिकताओं के आधार पर भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। साथ ही, लोकतांत्रिक शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मीडिया की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देना; मानवाधिकारों और कानून के शासन के लिए सम्मान; और प्रशांत देशों में न्याय तक पहुंच का विस्तार करना।[128]

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों अपने पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता और नाजुकता के बढ़ने से चिंतित हैं।

अमेरिका फिलहाल ओशिनिया क्षेत्र को पूरी तरह से अधिक गंभीरता से ले रहा है, जैसा कि 2020 में एक रक्षा सचिव द्वारा पलाऊ की पहली यात्रा सहित हाल की उच्च-स्तरीय यात्राओं से परिलक्षित होता है, जिसने बाद में अमेरिकी बेस और अमेरिकी विदेश मंत्री, एंटनी ब्लिंकेन की फ़िज़ी यात्रा की मेजबानी करने की पेशकश की - फरवरी 2022 में 36 वर्षों में इस तरह की पहली उच्च स्तरीय यात्रा। अमेरिका सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास फिर से खोलने की योजना बना रहा है। अमेरिका मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया (एफएसएम) और पलाऊ के साथ फ्री एसोसिएशन के कॉम्पेक्ट्स को नवीनीकृत करने के लिए भी बातचीत की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका का निर्णय "इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए, कॉम्पैक्ट वार्ता के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत की हालिया नियुक्ति और प्रशांत क्षेत्र में अपनी भौतिक राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने की प्रतिबद्धताओं में परिलक्षित होता है।

राष्ट्रपति बाइडन ने यूएस-पैसिफ़िक आइलैंड कंट्री समिट में प्रशांत आइलैंड्स के लिए 810 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की घोषणा की। शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार 'प्रशांत साझेदारी रणनीति' भी जारी की गई।

राष्ट्रपति बाइडन ने प्रशांत आइलैंड्स के साथ साझेदारी में अमेरिका की महत्वाकांक्षा को और अधिक बढ़ाने और संसाधनों के साथ उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने का संकल्प लिया है।[129]

हाल ही में, राष्ट्रपति बाइडन ने 28-29 सितंबर 2022 को वाशिंगटन, डीसी में अब तक के पहले 'यूएस-पैसिफ़िक आईलैंड कंट्री समिट' की मेजबानी की। राष्ट्रपति बाइडन और विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महामारी प्रतिक्रिया, आर्थिक सुधार, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और एक मुक्त और खुले इंडो-पैसिफ़िक को आगे बढ़ाने सहित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई।[130] शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, राष्ट्रपति बाइडन ने प्रशांत आइलैंड्स के लिए US$810 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की।[131] शिखर सम्मेलन के बाद पहली बार जारी की गई 'पैसिफ़िक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी' में उल्लेख किया गया कि प्रशांत आइलैंड्स के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यापक और गहन जुड़ाव बढ़ाना, इसकी विदेश नीति की प्राथमिकता है।[132]

अमेरिका पीआईएफ़ का डायलॉग पार्टनर है। पैसिफ़िक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी प्रशांत क्षेत्रवाद और पारदर्शी और जवाबदेह क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।[133] अगस्त 2021 में अमेरिका ने पीआईएफ़ समिट में पहली बार राष्ट्रपति के स्तर पर हिस्सा लिया था, जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने वर्चुअल समिट को संबोधित किया था। अगले वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 51वीं फ़ोरम की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका की "प्रशांत द्वीपों के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता" है ...

"हाल के वर्षों में, प्रशांत द्वीपों को शायद वह कूटनीतिक ध्यान और समर्थन नहीं मिला है जिसका क्षेत्र हकदार है, जो अब बदलने जा रहा है"। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अगले 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष US$60 मिलियन की घोषणा की।[134] उन्होंने यह भी घोषणा की कि अमेरिका पीआईएफ़ के लिए अपना पहला दूत नियुक्त करेगा और इस क्षेत्र में दो नए दूतावास स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा: टोंगा और किरिबाती में।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा, अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में चीन के बढ़ते निवेश और उसके कार्यों में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंता व्यक्त की है। अमेरिका-चीन संबंध पहले से ही काफी तनाव में रहे हैं और और ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका की दहलीज़ पर रणनीतिक चुनौती पेश करता है।[135] प्रशांत द्वीपों के साथ अमेरिका के संबंधों को सुरक्षा मुद्दों से परे जाने की जरूरत है। कांग्रेसमैन एड केस ने तर्क दिया है कि, प्रशांत आइलैंड्स में चीन की दिलचस्पी ने क्षेत्र के देशों को "एक भयानक स्थिति" में डाल दिया है, वे अमेरिका और उसके लोकतांत्रिक भागीदारों के साथ संबंधों को तरजीह देंगे लेकिन उनकी आर्थिक और ढांचागत विकास की जरूरतें उन्हें चीन के करीब धकेल रही हैं और यह एक भयानक विकल्प है।[136]

चाइना'ज़ एंगेजमेंट इन द पैसिफ़िक आइलैंड्स: इम्प्लीकेशंस फ़ॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नामक यूएस-चाइना इकोनॉमिक रिव्यू कमीशन (2018) की रिपोर्ट, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चीन हाल के वर्षों में प्रशांत द्वीप क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, अपने व्यापक राजनयिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित होकर, ताइवान के अंतरराष्ट्रीय स्थान को कम कर रहा है,

---

अमेरिका-चीन संबंध पहले से ही काफी तनाव में रहे हैं; और और ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका की दहलीज़ पर रणनीतिक चुनौती पेश करता है।

और कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर रहा है। वास्तव में, यह बताता है कि व्यापार, निवेश, विकास सहायता और पर्यटन डेटा की एक जांच से पता चलता है कि चीन इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गया है, जो अधिकांश क्षेत्रों में अमेरिका से काफी आगे है।[137]

यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी पेपर 2018 ने चेतावनी दी कि चीन अपने अंतरराष्ट्रीय दबदबे को बढ़ाने के लिए "परभक्षी अर्थशास्त्र" का उपयोग कर रहा है।[138] जून 2018 में, यूएस-चाइना इकोनॉमिक रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट जिसका शीर्षक चाइना'ज़ एंगेजमेंट इन द पैसिफ़िक आइलैंड्स: इम्प्लीकेशंस फ़ॉर द यूनाइटेड स्टेट्स था, में उल्लेख किया गया कि "चीन हाल के वर्षों में प्रशांत आइलैंड्स क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, अपने व्यापक राजनयिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित होकर, ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय स्थान को कम कर रहा है, और कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर रहा है।"[139] इसने इंगित किया कि क्षेत्र में संभावित आधार अमेरिकी रक्षा हितों और क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी भागीदारों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए चुनौती पेश कर सकता है।

द यूएस विजन फ़ॉर द इंडो-पैसिफ़िक (2020) इसे स्वीकार करता है कि अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत के पश्चिमी तट तक का क्षेत्र अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा हितों के केंद्र में है। फरवरी 2022 में घोषित संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम इंडो-पैसिफ़िक रणनीति, रेखांकित करती है कि राष्ट्रपति बाइडन के अधीन, अमेरिका अपने निकटतम सहयोगियों और साझेदारों के साथ, पूर्वोत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और ओशिनिया तक, प्रशांत आइलैंड्स सहित इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के हर कोने में अपनी दीर्घकालिक स्थिति और प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रणनीति पेपर इसे दोहराता है कि यह क्षेत्र विशेष रूप से अपनी आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के साथ चीन की जबरदस्ती और आक्रामकता के कारण बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि, अमेरिका प्रशांत आइलैंड्समें भागीदारों की रक्षा क्षमता

बनाने में भी मदद करेगा, और नए दूतावास खोलेगा तथा परामर्श, प्रशिक्षण, तैनाती और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया व प्रशांत आइलैंड्स में यूएस कोस्टगार्ड की उपस्थिति और सहयोग का विस्तार करेगा।[140]

हाल ही में जारी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2022 में उल्लेख किया गया है कि अमेरिका की "दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत आइलैंड्सपर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय राजनयिक, विकास और आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने" की योजना है"। ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और चीन का बलपूर्वक व्यवहार करना शामिल होगा।[141]

इन बयानों से साफ पता चलता है कि क्षेत्र में चीन की घुसपैठ से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका की उस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने में एक स्थायी रुचि है जहां यह क्षेत्र काफी हद तक अमेरिका के प्रभाव का एक क्षेत्र बना हुआ है जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपनी गठबंधन साझेदारी के अंतर्गत किया जाता है।

फ्रांस एक अन्य देश है जिसका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित है और वह इस क्षेत्र में तेजी से बदलते रणनीतिक संतुलन को लेकर चिंतित है। न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया सहित फ्रांस के पास दक्षिण प्रशांत में विदेशी क्षेत्र हैं, और देश इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में 2008-2021 से कुल समेकित फ्रांसीसी सहायता का अनुमान US$280.55 मिलियन था, जो बड़े पैमाने पर कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और शिक्षा क्षेत्रों में खर्च किया गया था।[142] अपने विशाल ईईजेड को देखते हुए,

अमेरिका की उस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने में एक स्थायी रुचि है जहां यह क्षेत्र काफी हद तक अमेरिका के प्रभाव का एक क्षेत्र बना हुआ है जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अपनी गठबंधन साझेदारी के अंतर्गत किया जाता है।

फ्रांस की इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और प्रशांत क्षेत्र पर निर्भरता पर फ्रांसीसी संप्रभुता की पुष्टि करने में रुचि है।[143] जुलाई 2021 में, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की फ्रेंच पोलिनेशिया की यात्रा था, द्वीप पर राष्ट्रपति की अब तक की पहली यात्रा। 2002 से नियमित 'फ्रांस-ओशिनिया शिखर सम्मेलन' आयोजित किया जाता है। पांचवां शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से 19 जुलाई 2021 को पोलिनेशिया के राष्ट्रपति की यात्रा से कुछ दिन पहले आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ़्रांस प्रशांत क्षेत्र के सभी पीआईसी'ज़ के नेताओं ने भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंता के प्रमुख मुद्दों पर ठोस बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, फ़ोरम प्रशांत और "ब्लू पैसिफ़िक" महाद्वीप के देशों में उपस्थिति के साथ पिछले यूरोपीय संघ के सदस्य देश के बीच एकमात्र नियमित उच्च स्तरीय बैठक है।[144] शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने घोषणा की कि फ्रांस और दक्षिण प्रशांत देश "परभक्षी" व्यवहार का मुकाबला करने हेतु, विशेष रूप से क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दक्षिण प्रशांत तट रक्षक नेटवर्क लॉन्च करेंगे।[145]

फ्रांसीसी रणनीतिकऔर राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा 2017 में इसका उल्लेख है कि फ्रांस की इस क्षेत्र के प्रमुख लोकतंत्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में रुचि है। यह इंगित करता है कि चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और गतिविधियों में रुझान "पूरे क्षेत्र की सुरक्षा डायनामिक्स को दोबारा बदल सकते हैं"।[146] 1992 के त्रिपक्षीय FRANZ समझौते के अंतर्गत प्रशांत आइलैंड्समें अपनी सहायता के समन्वय के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंध हैं। हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति के सामने अपने द्विपक्षीय संबंधों में नए सिरे से रुचि दिखाई है। यह उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान था कि 2 मई 2018 को गार्डन आइलैंड, सिडनी में बोलते हुए; फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हिंद-प्रशांत

क्षेत्र में संयुक्त उद्देश्यों के साथ क्षेत्र के लिए एक कुंजी के रूप में एक नई पेरिस-दिल्ली-कैनबरा ऐक्सिस का सुझाव दिया।[147] भारतीय और प्रशांत महासागर में एक निवासी शक्ति के रूप में फ्रांस स्वयं को "हिंद-प्रशांत के राष्ट्र" के रूप में पहचानता है।[148] इंडो-पैसिफ़िक 2019 पर फ्रांसीसी रणनीति इस बात पर जोर देती है कि, "हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एक रणनीतिक चुनौती" है और फ़्रांस से संबंधित क्षेत्र में संतुलन के रूप में 'सीधे और मूर्त रूप से' देश के लिए एक प्राथमिकता।[149] अद्यतन फ्रेंच इंडो-पैसिफ़िक स्ट्रैटेजी 2022, इस पर प्रकाश डालती है कि"हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गहन रणनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। चीन की शक्ति बढ़ रही है, और इसके क्षेत्रीय दावे अधिक से अधिक ताकत के साथ व्यक्त किए जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, यह पहले अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित थी, और अब सैन्य क्षेत्र में विस्तार कर रही है। ये सभी तत्व शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को बदल रहे हैं, और रणनीतिक गणनाओं को और अधिक जटिल बना रहे हैं।[150] यह प्रशांत आइलैंड्स क्षेत्र के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है।

फ़्रांस प्रशांत उपस्थिति देश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। न्यू कैलेडोनिया पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन भंडार के साथ-साथ दुनिया के कुल निकल के 30-40 प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फ्रेंच पोलिनेशिया रणनीतिक रूप से स्थित है। फ्रेंच पोलिनेशिया अकेले फ्रेंच ईईजेड का लगभग 45 प्रतिशत सृजित करता है।[151] ऐसे समय में जब ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता है,

---

फ़्रांस प्रशांत उपस्थिति देश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। फ़्रांस की इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और प्रशांत क्षेत्र पर निर्भरता पर फ़्रांस की संप्रभुता की पुष्टि करने में रुचि है।

इन संपत्तियों को नियंत्रित करना फ्रांस को क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति में रखता है।

जापान एक अन्य देश है जिसका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित है। जापान में आधिकारिक संवाद खाद्य, लकड़ी और ईंधन जैसे संसाधनों और समुद्री संसाधनों विशेष रूप से मत्स्य पालन के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रशांत आइलैंड्सक्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालता है। कई जापानी मछली पकड़ने के जहाज इस क्षेत्र में काम करते हैं। जापान के व्यापार की एक बड़ी मात्रा इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों से होकर गुजरती है।[152] जापान 1997 से हर तीन वर्ष में प्रशांत आइलैंड्स के नेताओं के साथ नियमित शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। ऐतिहासिक रूप से, जापान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहा है। जापान भी मानता है कि "उन द्वीपों में कई जापानी वंशज रहते हैं जिन पर जापान ने अतीत में शासन किया था"। जापान भी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है; 2008 से इस क्षेत्र को जापान की आधिकारिक सहायता US$36.44 बिलियन अनुमानित की गई है।[153] जापान ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताई है। हाल ही में, जापानी प्रधान मंत्री किशिदा ने 23 अप्रैल 2022 को जापान के कुमामोटो में चौथे एशिया-प्रशांत जल शिखर सम्मेलन में तुवालु के प्रधान मंत्री कौसा नाटानो से मुलाकात की। उन्होंने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को साकार करने के लिए क्षेत्र के देशों के साथ काम करने की जापान की प्रतिबद्धता को दोहराया और चीन-सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौते के बारे में भी चिंता व्यक्त की। पीएम किशिदा ने शिखर बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, जापान "रुचि के साथ (चीन की चाल को) बारीकी से देख रहा है"।[154]

जापान में आधिकारिक संवाद खाद्य, लकड़ी और ईंधन जैसे संसाधनों और समुद्री संसाधनों विशेष रूप से मत्स्य पालन के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रशांत आइलैंड्सक्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालता है।

5. दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की ओर भारत का दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में, पीआईसी'ज़ के प्रति भारत के दृष्टिकोण में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव आया है। विभिन्न भू-राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारकों के लिए इस परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नई दिल्ली ने इन छोटे द्वीपीय राष्ट्रों तक पहुंच बनाई है, जो अधिक जुड़ाव के प्रति सरकार की इच्छा को उजागर करता है। भारत ने भी बढ़ी हुई भौगोलिक पहुंच और रणनीतिक तत्व के साथ अपनी स्वंय की पुनर्नामित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को ध्यान में रखते हुए तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

परंपरागत रूप से, पीआईसी'ज़ सहित प्रशांत क्षेत्र को भारत की विदेश नीति में अधिक महत्व नहीं मिला। अब तक चौदह पीआईसी में से, भारत के पास केवल दो देशों, अर्थात् पापुआ न्यू गिनी और फ़िज़ी में निवासी मिशन हैं। ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र के साथ भारत का पारस्परिक व्यवहार 19वीं सदी की शुरुआत में, औपनिवेशिक युग से चला आ रहा है, जब भारतीय कामगारों को अनुबंधित बागान मजदूरों के रूप में काम करने के लिए दूसरे क्षेत्र, विशेष रूप से फ़िज़ी में ले जाया गया। पीआईसी के साथ भारत की बातचीत अभी भी काफी हद तक फ़िज़ी के साथ इसके जुड़ाव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुख्य रूप से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति से प्रेरित है; फ़िज़ी की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल की है और लगभग 3000 भारतीय पीएनजी में रहते हैं।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने द्वीप राष्ट्रों के लिए अनुदान सहायता और रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है जिसका उपयोग छोटे द्वीपीय देश सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं। भारत ने पीआईसी'ज़ को वार्षिक US$200,000 की सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। 2017-2018 के लिए पीआईसी'ज़ के साथ भारत का कुल वार्षिक व्यापार लगभग US$23.9 बिलियन था।[155] भारत ने पीआईसी के लघु और मध्यम उद्यम

(एसएमई) क्षेत्रों में भी समर्थन बढ़ाया है, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और आईटी के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों को भेजा है। तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, और क्षेत्र में चक्रवात के मामलों में मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति और अल्पकालिक नागरिक और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में भी सहायता मिली है।

इस क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण चीन से काफी अलग है और इसलिए इस क्षेत्र के देशों द्वारा इसका स्वागत किया गया है। भारत का दृष्टिकोण फ़िज़ी जैसे देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों पर अधिक पारदर्शी और समावेशी संबंध निर्माण पर केंद्रित है। भारत प्रशांत क्षेत्र में द्वीप देशों के लिए प्रतिबद्ध विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में भारत के प्रयास द्वीप देशों की प्राथमिकताओं द्वारा संचालित होते हैं। यह दृष्टिकोण 2014 में 'फ़ोरम फ़ॉर इंडो-पैसिफ़िक आइलैंड्स कोऑपरेशन' (एफआईपीआईसी) के गठन में परिलक्षित होता है, जहां न केवल सहायता और सहायता कार्यक्रमों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि मुद्दों पर सामूहिक चर्चा बल्कि व्यापार संबंधों में सुधार के मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हुई है। अब तक दो एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, पहला 2014 में फ़िज़ी में, उसके बाद 2015 में जयपुर, भारत में एफआईपीआईसी -II शिखर सम्मेलन हुआ। एफआईपीआईसी के तत्वावधान में नवीनतम कार्यक्रम 'इंडो-पैसिफ़िक आइलैंड्स सतत विकास सम्मेलन' था, जो मई 2017 में सुवा, फ़िज़ी में आयोजित किया गया था, जिसमें नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और आपदा की तैयारी के लिए अनुकूलन-शमन प्रथाओं के मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

भारत प्रशांत क्षेत्र में द्वीप देशों के लिए प्रतिबद्ध विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में भारत के प्रयास द्वीप देशों की प्राथमिकताओं द्वारा संचालित होते हैं।

एफआईपीआईसी ने स्पष्ट रूप से सहयोग के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करने और बहुआयामी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और पीआईसी'ज़ को एक मंच प्रदान किया है।

सितंबर 2019 में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर न्यूयॉर्क में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रशांत आइलैंड्स के विकासशील देशों के नेताओं के साथ बहुपक्षीय प्रारूप में मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पीआईसी'ज़ के साझा मूल्य और एक साझा भविष्य है, और भारत "पीआईसी'ज़ की विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है"।[156] भारत ने उनकी अपनी पसंद के क्षेत्र में उच्च प्रभाव विकासात्मक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए US$12 मिलियन के अनुदान (प्रत्येक प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों [पीएसआईडीएस] को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के आवंटन की भी घोषणा की। इसके अलावा, US$150 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट जिसका लाभ पीएसआईडीएस द्वारा सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने वाले कुछ क्षेत्रीय देशों के निर्णय का स्वागत किया और प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को गठबंधन फ़ॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।

क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय खिलाड़ियों के हितों और सरोकारों के अलावा, हाल के तेज भू-राजनीतिक परिवर्तनों के साथ, पीआईसी'ज़ बहुपक्षीय जुड़ावों के एजेंडे में भी जगह पा रहे हैं। इससे पहले 2022 क्वाड इन-पर्सन लीडर्स समिट में चार देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि सदस्य समुद्री डोमेन जागरूकता और जलवायु प्रतिक्रियाओं में सुधार करने और अपनी साइबर सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रशांत आइलैंड्समें उच्च मानक बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहयोग करेंगे। हाल के वर्षों में, इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र क्वाड और विभिन्न त्रिपक्षीय संवादों जैसे कई मिनीलेटरल के उदय के साथ नई व्यवस्था देख रहा है। भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया हाल ही में शुरू की गई

एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय पहल है; भारत, जापान और फ्रांस त्रिपक्षीय के बारे में भी बातचीत हो रही है, और एक नई सुरक्षा त्रिपक्षीय AUKUS की घोषणा भी हो रही है। इन सभी घटनाक्रमों का दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए, स्पष्ट रूप से प्रशांत क्षेत्र में द्वीप पारंपरिक और नए खिलाड़ियों से ध्यान आकर्षित करते हैं, इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक स्थिति प्रवाह में प्रतीत होती है और इस मंथन के निकट भविष्य में बने रहने की संभावना है।

निष्कर्ष

इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र, जिसकी विशेषता, 'अफ्रीका के तटों से अमेरिका के तटों तक', अनिवार्य रूप से विशाल समुद्री भूगोल है, क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन अनिश्चित दिखने के साथ प्रतिस्पर्धा का स्थान तेज़ी से बनता जा रहा है। वैश्वीकरण और वैश्विक आर्थिक समृद्धि दुनिया के प्रमुख महासागरों के रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मुक्त और खुले समुद्री वाणिज्य के साथ काफी हद तक पनपती है। खाद्य, ऊर्जा और खनिजों के लिए समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निर्भरता आने वाले वर्षों में ही बढ़ेगी। इसलिए, इन मूल्यवान संसाधनों को हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ द्वीपीय राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे न केवल विशाल समुद्री क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत हैं, बल्कि अपतटीय रक्षा रणनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, समुद्री शक्ति के वितरण में बदलाव काफी हद तक इंडो-पैसिफ़िक के रणनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा। पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। प्रशांत क्षेत्र में द्वीप जो युद्ध के बाद की अवधि में वैश्विक भू-राजनीति की परिधि पर रहे हैं, प्रमुख शक्तियों का ध्यान बढ़ते हुए देख रहे हैं।

साथ ही, उन्हें कई गैर-पारंपरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सामूहिक सुरक्षा की तमाम बहस के बीच असली चुनौती शक्ति का एक विश्वसनीय संतुलन बनाए रखना है।

अधिकांश द्वीप देशों के लिए अत्यधिक प्रतिकूल शर्तों पर चीन के सहायता कार्यक्रम और ऋण वास्तविक लाभ देने के वादे के बिना, उनकी आर्थिक स्थिरता को चुनौती देते हैं और उन्हें बढ़ते कर्ज के दबाव में डाल देते हैं। जैसा कि किसी जगह हुआ है, बीजिंग के निवेश ज्यादातर मामलों में तुच्छ और अपर्याप्त रूप से नियोजित हैं। हंबनटोटा, ग्वादर और अन्य जगहों के उदाहरणों को देखते हुए, अधिकांश चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और भू-राजनीतिक निहितार्थों के बारे में चिंताएँ उभर रही हैं। पारंपरिक क्षेत्रीय खिलाड़ियों का डर यह है कि, जैसा कि कहीं और अधिकांश परियोजनाओं के मामले में होता है, इस बात की भी संभावना है कि जो द्वीप देश पहले से ही कर्ज के दबाव और खराब आर्थिक स्थिति में हैं, हो सकता है कि चीन को भारी लागत मूल्य चुकाने में सक्षम न हों और और इसलिए चीन के लिए रणनीतिक बुनियादी ढांचे का नियंत्रण छोड़ दें, जिसका परिणाम क्षेत्र में बीजिंग की सक्रिय सैन्य उपस्थिति हो। उनका मानना है कि बीजिंग द्वारा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा विकास का पूरा विचार, स्पष्ट रूप से यह एक बहाना है जिसके पीछे चीन का दीर्घकालिक उद्देश्य स्वयं को भारतीय और प्रशांत महासागरों दोनों में, एक पूर्व-प्रतिष्ठित समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

कई पीआईसी'ज़ के लिए, चीन से सहायता ऐसे समय में आई है जब वे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर से थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जबकि ये छोटे द्वीप निवेश की जरूरतों की तलाश में हैं जिन्हें एक या दो प्रमुख शक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, हालाँकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे "जहां उनकी रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रहने की अधिक संभावना है" उसका आकलन करें।[157]

कुछ पीआईसी दिखा रहे हैं कि वे अब प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों में विशिष्टता नहीं चाहते हैं। क्षेत्र में तनाव जो पहले ताइवान और चीन पर अधिक केंद्रित था, अब प्रमुख शक्तियों के बीच भू-रणनीतिकप्रतिस्पर्धा में बढ़ रहा है। वर्तमान पृष्ठभूमि को देखते हुए, क्षेत्रीय और बाह्य-क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बढ़ते हितों के साथ, इस क्षेत्र के आने वाले समय में एक तेजी से प्रतिस्पर्धी रणनीतिक स्थान बनने की संभावना है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि छोटे द्वीप देश बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में बाधाओं को पार करते हुए किस प्रकार रास्ता बनाते हैं।

एंडनोट्स

[1] Gearóid Ó Tuathail and Simon Dalby (ed.), "Rethinking Geopolitics", 2002, p. 2, Routledge, London and New York.
[2] John C. Dorrance, "The Soviet Union and the Pacific Islands: A Current Assessment." Asian Survey, vol. 30, no. 9(1990), pp. 908–25, JSTOR, https://doi.org/10.2307/2644529. Accessed 26 August 2022.
[3] Ibid, no.1 p. 6
[4] David Scott, "Small Island Strategies in the Indo-Pacificइंडो-पैसिफ़िक by Large Powers" The Journal of Territorial and Maritime Studies, vol. 8, no. 1 (Winter/Spring 2021), pp. 66-85
[5] Shankari Sundararaman, "Diplomatic Outreach to Small States in Indian Ocean", 1 December 2020,https://www. newindianexpress.com/opinions/2020/dec/01/diplomatic-outreach-to-small-statesin-indian-ocean-2230233. html, Accessed on July 22, 2022
[6] Cleo Paskal, Strategic Overview of Oceania, https://www.eastwestcenter.org/publication/strategic-overview-oceania, Accessed on July 19, 2022.
[7] Tevita Motulalo, "India's Strategic Imperative in the South Pacific Opportunities and Challenge", Gateway House Report, October 2013, http://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2013/11/Indias-Strategic-Imperative-in-the-South-Pacific.pdf
[8] Pacific Island Forum, Forum Members, Pacific Islands Forum Secretariat, https://www.forumsec.org/niue-2/, Accessed on June 24, 2022
[9] World Bank, Country Cooperation Strategy at a Glance, " pacific Island Countries", chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136831/ccsbrief_pci_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Accessed on July 29
[10] World Bank, Country Cooperation Strategy at a Glance, " pacific Island Countries", chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136831/ccsbrief_pci_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Accessed
[11] R. Gerard. Ward, "South Pacific Island Futures: Paradise, Prosperity, or Pauperism?" The Contemporary Pacific 5, no. 1 (1993): 1–21. http://www.jstor.org/stable/23699868
[12] Kiribati, Pacific Islands Forum Secretariat, http://www.forumsec.org/kiribati/, Accessed on July 19, 2022
[13] Colin Flint, "Introduction to Geopolitics", p. 15, Routledge, London, 2021
[14] Gearóid O'Tuathail, "Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space", Routledge London, 1996, p. 277
[15] Gregory E. Fry, "Regionalism and International Politics of the South Pacific." Pacific Affairs 54, no. 3 (1981) pp. 455–84. https://doi.org/10.2307/2756789
[16] I. bid, no.1, p. 6
[17] C. Pan, M. Clarke, "Narrating the South Pacific in and Beyond Great Power Politics", East Asia 39, 2022, pp.1–11.
[18] I.bid
[19] Richard Ullman, "Redefining Security", International Security, vol. 8, no. 1, Summer, 1983, p.129
[20] United Nations General Assembly (2004), A More Secure World: Our Shared Responsibility, Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, fifty-ninth session, Agenda item 55, Follow-up to the outcome of the Millennium Summit 2, UN Doc A/59/565, December 2004, https://www1.umn.edu/humanrts/ instree/report.pdf, Accessed on November 7, 2022
[21] Fiji Pushes for Greater Finance to Promote Food Security in Response to Rising Seas, FijiSun Online, February 20, 2018, http://fijisun.com.fj/2018/02/20/fiji-pushes-for-greater-finance-to-promote-food-security-in-response-to-rising-seas

[22] I bid

[23] PM: Leaders Must Fight Climate Action with Pacific Spirit, Fiji Sun, 27 July 2018, https://fijisun.com.fj/2018/07/27/ pm-leaders-must-fight-climate-action-with-pacific-spirit/?fbclid=IwAR2obTpNG-PtkVJV5UyULTe3d2R_c_5LTc0u6Ff_v6FtEIqRoY9CStdqbec, Acc

[24] The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent, PIF, https://www.forumsec.org/2050strategy/, Accessed on July 19, 2022.

[25] Boe Declaration on Regional Security, https://www.forumsec.org/boe-declaration-on-regional-security/

[26] Denise Fisher, "France in the South Pacific: Power and Politics", ANU Press, 2013, Canberra, pp. 1-3

[27] I bid

[28] Stewart Firth, "Instability in the Pacific Islands: A Status Report", 4 June 2018, Lowy Institute, https://www.lowyinstitute.org/publications/instability-pacific-islands-status-report

[29] I bid.

[30] R. Gerard. Ward, "South Pacific Island Futures: Paradise, Prosperity, or Pauperism?" The Contemporary Pacific 5, no. 1 (1993), pp.1–21. http://www.jstor.org/stable/23699868

[31] Rani D Mullen and Kailash Parsad, "India- Pacific Islands Brief", November, 2014, Indian Development Cooperation Research, Centre for Policy Research, p. 4

[32] Barefoot Grandmothers Electrify Rural Communities, 04 November2012, https://www.barefootcollege.org/barefoot-grandmothers-electrify-rural-communities/

[33] Training Workshop on Sustainable Development for Pacific Islands Forum Countries in Suva, Fiji Islands, https://www.teriin.org/project/training-workshop-sustainable-development-pacific-islands-forum-countries-suva-fiji-islands , Accessed on 30 August 20

[34] See Jonathan Schultz, Overseeing and Overlooking: Australian Engagement with the Pacific Islands (1988-2007), (PhD Thesis, School of Social and Political Science, The University of Melbourne, 2012) in Wesley Morgan and Tess Newton Cain, "Activating greater trade and investment between Australia and Pacific island countries", Policy Brief, Griffith Asia Institute, June 2020, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0022/1083154/pacific-trade-policy-brief-9-6-20.pdf, p. 2,Accessed on 3 November 2022

[35] Ibid

[36] Pacific Islands Forum on brink of collapse over leadership dispute, 8 February 2021, https://amp.smh.com.au/ politics/federal/pacific-islands-forum-on-brink-of-collapse-over-leadership-dispute-20210208-p570iw.html, Accessed on August 1, 2022

[37] Asia & Pacific Department, IMF, Pacific Islands Monitor ISSUE 15 October 2021, pp. 2-6

[38] I bid

[39] The Mapping Foreign Assistance in the Pacific Project, Lowy Institute for International Policy, https://chineseaidmap.lowyinstitute.org/, Accessed on August 1, 2022

[40] Lowy Institute, Pacific Aid Map, 2021, https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/, Accessed on August 1, 2022

[41] RPT-INSIGHT-Payment due: Pacific islands in the red as debts to China mount, 13 July 2018, https://www.reuters. com/article/pacific-debt-china/rpt-insight-payment-due-pacific-islands-in-the-red-as-debts-to-china-mountidUSL4N1UQ6GA, Accessed on July 27, 2022

[42] TONGA: Debt Sustainability Analysis Update, Country Report, International Monetary Fund, De4cember 18, 2020, https://www.imf.org/-/media/Files/DSA/external/pubs/ft/dsa/pdf/2021/dsacr2126.ashx, Accessed on July 30, 2022

[43] Tonga Discusses Debt with China, Australia's Wong to Visit, https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-06-01/australias-foreign-minister-to-travel-to-tonga-on-friday-tonga-government, July 1, 2022, Accessed on July 27, 2022

[44] Vanuatu - Joint World Bank-IMF Debt Sustainability Analysis, June 2019, Prepared jointly by the staffs of the International Development Association (IDA) and the International Monetary Fund (IMF), https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/32563, Accessed on July 27, 2022

[45] Release: US $1.08m for Pacific in China-Pacific Islands Forum annual development cooperation ceremony, PIF, https://www.forumsec.org/2022/08/25/release-us-1-08m-for-pacific-in-china-pacific-islands-forum-annual-development-cooperation-ceremony/, Accessed on July 2

[46] Fact Sheet: Cooperation between China and Pacific Island Countries, 24 May 2022, Ministry of Foreign Affairs, PRC,

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html, Accessed on July28, 2022

[47] Article by Ambassador Zhang Ping Entitled "Closer Co-Operation under Belt And Road Win-Win for Fiji, China", Chinese Embassy in Fiji,17 May, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/ t1462445.shtml, Accessed on July 28, 2022

[48] Fact Sheet: Cooperation between China and Pacific Island Countries, 24 May 2022, Ministry of Foreign Affairs, PRC, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html, Accessed on August 18, 2022

[49] BRI paves way for China-Pacific islands cooperation, Xinuha, https://www.chinadailyhk.com/articles/28/173/13/1542535066071.html, November 1

[50] Ben Wan Beng Ho, "The Strategic Significance of Manus Island for the U.S. Navy", Vol. 144/12/1,390, December 2018, https://www.usni.org/magazines/proceedings/2018/december/strategic-significance-manus-island-us-navy, Accessed on August 1, 2

[51] Thomas Shugart, "A Chinese-built airport next door to a key Australia-US naval base?", The Interpreter, 7 August 2020, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/chinese-built-airport-next-door-australia-us-funded-navyport, Accessed on August 10, 2022

[52] U.S. joins Australian plan to develop new Pacific naval base, https://www.reuters.com/article/us-apec-summit-port-idUSKCN1NM06X, Accessed on Au

[53] China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications, 9 April 2018 https://www.smh.com.au/ politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html,Accessed on August 17, 2022

[54] Pacific Aid map, Lowy Institute, https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/, Accessed on August 17, 2022.

[55] David Wroe, "China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications", Sydney Morning Herald, 9 April 2018, https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-globalramifications-20180409-p4z8j9.html, Accessed on Aug 17,2022

[56] Ibid. no. 54

[57] Ibid. no. 54

[58] Richard K. Pruett, "A United States-Kiribati Compact of Free Association Would Yield Mutual Dividend", Asia Pacific Bulletin, No. 501, March 2020,https://www.eastwestcenter.org/publications/united-states-kiribati-compact-free-association-would-yield-mutual-dividends#:~:text=Kiribati%20is%20a%20Pacific%20Micronesian,Micronesia%2C%20and%20the%20Marshall%20Islands.&text=Each%20is%20now%20a%20sovereign,law%20 equal%20to%20the%20Constitution, Accessed on July 28, 2022

[59] China Is Leasing an Entire Pacific Island. Its Residents Are Shocked, 16 October 2019, https://www.nytimes. com/2019/10/16/world/australia/china-tulagi-solomon-islands-pacific.html, Accessed on July 13, 2022

[60] Solomon Islands PM survives no-confidence vote after weeks of protest, https://www.theguardian.com/ world/2021/dec/06/solomon-islands-pm-survives-no-confidence-vote-after-weeks-of-protest, Accessed on July 18, 2022.

[61] Srijan Shukla, "Two phrases critics of China's BRI must not use – debt trap & threat to sovereignty", The Print, 2019, https://theprint.in/opinion/two-phrasescritics-of-chinas-bri-must-not-use-debt-trap-threat-to-sovereignty/229544/, Accessed on July

[62] Military-Civil Fusion and PRC, US Department of States, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/What-is-MCF-One-Pager.pdf, Accessed on August 12, 2022

[63] Alex Stone, Peter Wood, "China's Military-Civil Fusion Strategy", 2015, China Aerospace Studies Institute, Air University, Maxwell AFB, AL, https://www.airuniversity.af.edu/CASI/Display/Article/2217101/chinas-military-civil-fusion-strategy/, Accessed on August 7, 2022

[64] GVC Naidu, "India and Maritime Silk Road", in Manish (ed.), The Belt and Road Initiative: Implications for India, 2021, Pentagon Press, New Delhi

[65] Assessing the Risks of Chinese Investments in Sub-Saharan African Ports, Centre for Strategic and International Studies, 4 June 2019, at https://www.csis.org/ analysis/assessing-risks-chinese-investments-sub-saharan-african-ports, Accessed on August 15, 2022.

[66] Zongyuan Zoe Liu, "What the China-Solomon Islands Pact Means for the U.S. and South Pacific", 4 May 2022, https://www.cfr.org/in-brief/china-solomon-islands-security-pact-us-south-pacific, Accessed on August 8, 2022

[67] The First China-Pacific Island Countries Forum on Fishery Cooperation and Development Held, 12 December 2021, http://english.moa.gov.cn/news_522/202112/t20211210_300762.html, Accessed on August 8, 2022

[68] Xi Jinping Delivers Written Remarks at the Second China-Pacific Island Countries Foreign Ministers' Meeting, 30 May 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220530_10694608.html, Accessed on July 31, 2022

[69] Fact Sheet: Cooperation between China and Pacific Island Countries, 2022-05-24, Ministry of Foreign Affairs, PRC, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html, Accessed on July 28, 2022

[70] Text of 'Framework Agreement on Security Cooperation', https://twitter.com/AnnaPowles/status/1506845794728837120/photo/4

[71] Twitter, https://twitter.com/AnnaPowles/status/1506845794728837120/photo/2

[72] I bid

[73] We needed China deal to protect 'domestic security', says key Solomon Islands official, 14 June 2022, https:// www.theguardian.com/world/2022/jun/14/we-needed-china-deal-to-protect-domestic-security-says-key-solomon-islands-official, Accessed on July 28, 2022

[74] Agreement with China not in national interest says Solomons opposition leader, 28 March, 2022,https:// www.rnz.co.nz/international/pacific-news/464019/agreement-with-china-not-in-national-interest-says-solomons-opposition-leader, Accessed on August 5, 2022

[75] I bid

[76] Solomon Islands PM survives no-confidence vote after weeks of protest, https://www.theguardian.com/ world/2021/dec/06/solomon-islands-pm-survives-no-confidence-vote-after-weeks-of-protest, Accessed on August 2, 2022

[77] Statement by NSC Spokesperson Adrienne Watson on U.S. Consultations with Australia, Japan, and New Zealand in Honolulu, April 19, 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/19/ statement-by-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-u-s-consultations-with-australia-japan-and-new-zealand-in-honolulu/, Accessed on August 7, 2022

[78] Readout of Senior Administration Travel to Hawaii, Fiji, Papua New Guinea, and Solomon Islands, April 22, 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/22/readout-of-senior-administration-travel-to-hawaii-fiji-papua-new-guinea-and-solomon-islands

[79] I bid

[80] Scott Morrison pushes back on claims the government bungled security relationship with Solomon Islands, 20 April 2022, https://www.abc.net.au/news/2022-04-20/solomon-islands-china-pact-failure-foreign-policy-labor/101000878, Accessed on July 31, 2022

[81] Scott Morrison says Chinese military base in Solomon Islands would be 'red line' for Australia, US, 24 April 2022,https://www.abc.net.au/news/2022-04-24/scott-morrison-china-naval-base-solomon-islands-redline/101011710, Accessed on July 27,2022

[82] I bid. no. 36

[83] Doorstop interview, Suva, Fiji, https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/transcript/doorstop-interview-suva-fiji, Acce

[84] Australian PM Albanese 'very confident' there will be no Chinese bases in Solomon Islands, https://www. theguardian.com/australia-news/2022/jul/14/australia-pm-anthony-albanese-very-confident-no-chinese-bases-china-solomon-islands-pif-pacific-islands-forum ,Accessed on July 29,2022

[85] Jacinda Ardern: There is no need for Solomons-China agreement, 20 Apr, 2022, https://www.nzherald.co.nz/nz/ politics/jacinda-ardern-there-is-no-need-for-solomons-china-agreement/QZ7DGGNCHV6RO5JXFDVD5LERK4/, Accessed on July 27, 2022.

[86] Pacific Islands Forum 2022: Leaders set to issue statement on China, United States, security, climate change and unity issues, 14 Jul, 2022, https://www.nzherald.co.nz/nz/pacific-islands-forum-2022-leaders-set-to-issue-statement-on-china-united-states-security-climate-change-and-unity-issues/GVRZMK4WI6LGN3GS7AD533QWOE/, Accessed on July 27, 2022.

[87] Kiribati's exit from Pacific Forum not a sign of wider disunity - Jacinda Arder, 11 July, 2022, https://www.rnz. co.nz/news/political/470737/kiribati-s-exit-from-pacific-forum-not-a-sign-of-wider-disunity-jacinda-ardern, Accessed on July 27, 2022

[88] Solomon Islands refuses to allow U.S. ship to make port call, 27 August 2022, https://www.japantimes.co.jp/news/2022/08/27/asia-pacific/solomon-islands-us-coast-guard-refusal/, Accessed on 15 September 2022.
[89] ARGOUNèS Fabrice, « L'Australie : la tentation de la puissance régionale », Pouvoirs, 2012/2 (n° 141), pp. 103-116, DOI : 10.3917/pouv.141.0103, https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2012-2-page-103.htm, Accessed on July 19, 2022
[90] Australia, U.S. Set to Expand Papua New Guinea Naval Base, November 23, 2018, https://news.usni.org/2018/11/23/australia-u-s-set-expand-papa-new-guinea-naval-base , Accessed on July 19, 2022.
[91] I bid.
[92] China eyes Vanuatu military base in plan with global ramifications, 9 April 2018 https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html, Accessed on July 19, 2022.
[93] Vanuatu foreign minister denies China military base claim, 10 April 2018, https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/354699/vanuatu-foreign-minister-denies-china-military-base-claim, Accessed on July 19, 2022.
[94] 'Great concern': Malcolm Turnbull draws a line in the sand on military bases near Australia, Sydney Morning Herald, 10 April 2018, https://www.smh.com.au/politics/federal/great-concern-malcolm-turnbull-draws-a-linein-the-sand-on-military-bases-near-australia-20180410-p4z8t3.html, Accessed on June 22, 2022.
[95] Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Media Release, 19 June 2018, https://foreignminister.gov.au/ releases/Pages/2018/jb_mr_180619.aspx, Accessed on July 28, 2022.
[96] Australia supplants China to build undersea cable for Solomon Islands, 13 June 2018, https://www.theguardian. com/world/2018/jun/13/australia-supplants-china-to-build-undersea-cable-for-solomon-islands, Accessed on July 28, 2022.
[97] Richard Herr, Australia-Fiji Relations in 2018: Finding A New Normal, 26B, march 2018, https://www.eastwestcenter.org/publications/australia-fiji-relations-in-2018-finding-new-normal, Accessed on August 8, 2022
[98] Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 'Republic of the Fiji Islands Country Brief', https://www.dfat. gov.au/geo/fiji/fiji-country-brief , Accessed on August 8, 2022.
[99] S Smith (Minister for Foreign Affairs), 'Joint press conference with Minister for Immigration, Chris Evans; Minister for Home Affairs, Bob Debus', 14 April 2009, http://www.foreignminister.gov.au/transcripts/2009/090414_jpc. html
[100] I bid. no. 71
[101] Tess Newton Cain, "Pacific Perspectives on the World Listening to Australia's Island Neighbours in Order to Build Strong, Respectful and Sustainable Relationships" Whitlam Institute Research Project, February 2020, https://www.whitlam.org/publications/2020/2/13/pacific-perspectives-on-the-world, Accessed on 4 November 2022
[102] I bid. no. 71
[103] Pacific Agreement on Closer Economic Relations Plus, https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/pacer/pacific-agreement-on-closer-economic-relations-plus , Accessed on August 8, 2022.
[104] Bateman and Galdorisi (2013), "Promoting Australia as a Maritime Power: The Significance of the Law of the Sea", in Andrew Forbes (ed.) The Naval Contribution to National Security and Prosperity, Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2012, pp.108-109, Sea Power Centre, Canberra, ,http://www.navy. gov.au/sites/default/files/documents/SP12.pdf, Accessed 07 December 2021
[105] Australian Government, Department of Defence White Paper 2013, pp. 2-11, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust/2013, Accessed on July 28, 2022.
[106] Australian Government, Defence White Paper 2016,https://www.defence.gov.au/about/publications/2016-defence-white-paper, Accessed on July 28, 2022.
[107] 107 Australian Government, Defence Strategic Update 2002, https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update, Accessed on July 25, 2022
[108] Marise Payne , Twitter, https://twitter.com/dfat/status/1251757189154385920
[109] China country brief, Bilateral relations, https://www.dfat.gov.au/geo/china/china-country-brief#:~:text=Trade%20and%20investment,-China%20is%20Australia's&text=Two%2Dway%20trade%20with%20China,per%20cent%20compared%20to%202019, Accessed on July 17, 2022.

[110] 110 Stepping-up Australia's Pacific engagement, https://dfat.gov.au/geo/pacific/engagement/Pages/stepping-up-australias-pacific-engagement.aspx, Accessed on July18, 20

[111] Strengthening Australia's commitment to the Pacific, 8 November 2018,

[112] PACER Plus is a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) covering goods, services and investment. Negotiations on the agreement commenced in 2009 and concluded in Brisbane on 20 April 2017. See for details:https:// dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/pacer/Pages/pacific-agreement-on-closer-economic-relations-pacer-plus.aspx , Accessed on May 19, 2022

[113] Strategic Defence Policy statement, 2018 p. 22 and 24, http://www.nzdf.mil.nz/downloads/pdf/public-docs/2018/strategic-defence-policy-statement-2018.pdf, Accessed on July 1, 2022.

[114] Our relationship with the Pacific, New Zealand Department of Foreign Affairs and Trade, https://www.mfat.govt. nz/en/countries-and-regions/pacific/, Accessed on June 25, 2022.

[115] Our aid partnerships in the Pacific, https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-work-in-the-pacific/

[116] Pacific Reset picks up pace, 8 November 2018, https://www.beehive.govt.nz/release/pacific-reset-picks-pace, Accessed on May 19, 2022.

[117] Australia and New Zealand announce joint Pacific Cyber cooperation, 16 November 2018, https://www.beehive. govt.nz/release/australia-and-new-zealand-announce-joint-pacific-cyber-cooperation, Accessed on May 1, 2022.

[118] New Zealand Department of Foreign Affairs and Trade, "Our aid partnerships in the Pacific, https://www.mfat. govt.nz/en/aid-and-development/our-aid-partnerships-in-the-pacific/, Accessed on July10, 2022.

[119] I bid no. 99

[120] I bid. no. 96

[121] An address by New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, 7July 2022, https://www.lowyinstitute.org/publications/address-new-zealand-prime-minister-jacinda

[122] NZ's Ardern Urges Diplomacy with China Over Pacific Tensions, 7 July 2022, https://www.bloomberg.com/news/ articles/2022-07-07/nz-s-ardern-urges-diplomacy-with-china-over-pacific-tensions, Accessed on August 1, 2022.

[123] New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern warns NATO of China's rising assertiveness, 30 June 2022, https:// www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3183579/new-zealand-prime-minister-jacinda-ardern-warns-nato-chinas, Accessed on July1, 2022.

[124] We don't need to be reactive': New Zealand keeps faith in its foreign policy amid China Pacific push, 3 June 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/we-dont-need-to-be-reactive-new-zealand-keepsfaith-in-its-foreign-policy-amid-china-pacific-push, Accessed on July 5, 202

[125] Joint Readout of Meeting Between Prime Minister Ardern and Vice President Harris, May 31, 2022, https://www. whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/31/joint-readout-of-meeting-between-primeminister-ardern-and-vice-president-harris/, Accessed on August 1, 2022

[126] Remarks by President Bidenबाइडन and Prime Minister Jacinda Ardern of New Zealand before Bilateral Meeting, May 31, 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/05/31/remarks-by-president-Bidenबाइडन-and-prime-minister-jacinda-ardern-of-new-zealand-before-bilateral-meeting/, Accessed on August 1, 2022.

[127] Joint Statement by President Biden and Prime Minister Jacinda Ardern of Aotearoa New Zealand—A 21st-Century Partnership for the Pacific, the Indo-Pacific, and the World, May 31, 2022, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/joint-statement-president-Biden-and-prime-minister-jacinda-ardern-aotearoa-new-zealand, Accessed on July 31, 2022

[128] I bid

[129] I bid

[130] U.S.-Pacific Island Country Summit, September 28-29, 2022 in Washington, D.C., https://www.state.gov/u-s-pacific-islands-country-summit/#:~:text=President%20Biden%20hosted%20the%20first,people%2Dto%2Dpeople%20 ties, Accessed on 7 October 2022.

[131] Remarks by President Biden at the U.S.-Pacific Island Country Summit, September 29, 2022, https://www. whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/29/remarks-by-president-biden-at-the-u-s-pacificisland-country-summit/

[132] Fact Sheet: President Biden Unveils First-Ever Pacific Partnership Strategy, The White House, September 29, 2022https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/29/fact-sheet-president-Biden-unveils-first-ever-pacific-partnership-strategy/ , Access
[133] I bid.
[134] Remarks by Vice President Harris at the Pacific Islands Forum, July 12, 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/07/12/remarks-by-vice-president-harris-at-the-pacific-islands-forum, Accessed on July 30, 2022
[135] Ashish Kumar Sen. "A Rising China Has Pacific Islands in Its Sights" United States Institute of Peace, 23 July 2020, https://www.usip.org/publications/2020/07/rising-china-has-pacific-islands-its-sights, Accessed on July 30, 2022.
[136] I bid.
[137] China's Engagement in the Pacific Islands: Implications for the United States, 14 June 2018, chrome-extension:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China-Pacific%20 Islands%20Staff%20Report.pdf, Accessed on June 25, 2022.
[138] US National Defence Strategy Paper, 2018, P. 2, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf, Access
[139] China's Engagement in the Pacific Islands: Implications for the United States, January 2018, https://www.uscc. gov/sites/default/files/Research/China-Pacific%20Islands%20Staff%20Report.pdf, Accessed on June 28, 2022.
[140] Indo-Pacific Strategy of the United States , 22 February 2022, The White House, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf, Accessed on June 25, 2022.
[141] United States, "National Security Strategy", The White House, October 12, 2022, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.p
[142] I bid, no. 41
[143] Nic Macllenan, France and the Blue Pacific, 30 April 2018, Asia and the Pacific Policy Studies, vol. 5, no. 3, p. 428.
[144] Multilateralism at work: the France-Oceania Summit, 3 August 2021,https://www.spc.int/updates/blog/blog/2021/08/multilateralism-at-work-the-france-oceania-summit, Accessed on, 1November 2022
[145] France, South Pacific nations to combat 'predatory' fishing as China extends reach 19 July 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/france-south-pacific-nations-combat-predatory-fishing-china-extends-reach-2021-07-19/ Accessed on 7 November 2022.
[146] French Defence and National Security Review, 2017, p. 44, file:///C:/Users/GEM/Desktop/DEFENCE+AND+NATIONAL+SECURITY+STRATEGIC+REVIEW+2017.pdf, Accessed on 10 May 2022.
[147] Macron wants strategic Paris-Delhi-Canberra axis amid Pacific tension, May 3, 2018, https://www.reuters.com/ article/us-australia-france/macron-wants-strategic-paris-delhi-canberra-axis-amid-pacific-tension-idUSKBN1I330F
[148] I bid. no. 4
[149] French Strategy in the Indo-Pacific "For an Inclusive Indo-Pacific", 2019, https://www.diplomatie.gouv.fr/en/ country-files/asia-and-oceania/the-Indo-Pacific-region-a-priority-for-france/
[150] France's Indo-Pacific Strategy, 2022, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_dcp_a4_indopacifique_022022_v1-4_web_cle878143.pdf, Accessed on 10, May 2022.
[151] Denise Fisher, "France in the South Pacific: Power and Politics", ANU Press, 2013, pp. 5-6.
[152] Why the Pacific Island Countries are important to Japan?, Ministry of Foreign Affairs of Japan, https://www.mofa. go.jp/region/asia-paci/spf/palm2003/relation.html
[153] Ibid. no.51
[154] Kishida, Leaders of Cambodia, Laos, Tuvalu Affirm Cooperation on Ukraine Politics, April 23, 2022, https://www. nippon.com/en/news/yjj2022042300480/, Accessed on 7 November 2022.
[155] Department of Commerce, Export Import Data Bank, Ministry of Commerce and Industry, http://commerce-app. gov.in/eidb/
[156] Prime Minister Meets Pacific Island Leaders, 25 September 2019, https://www.narendramodi.in/pm-s-remarksat-india-pacific-islands-leaders-meeting-546591

[157] Shankari Sundararaman, "Diplomatic Outreach to Small States in Indian Ocean", 1 December 2020, https://www. newindianexpress.com/opinions/2020/dec/01/diplomatic-outreach-to-small-statesin-indian-ocean-2230233. html, Accessed on 7 June 2022.

डॉ. प्रज्ञा पांडे भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए), सप्रू हाउस, नई दिल्ली में रिसर्च फ़ैलो हैं। वह समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर, इंडो-पैसिफ़िक और क्षेत्रीय भू-राजनीति से संबंधित मुद्दों की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर विस्तार से लिखा है। आईसीडब्ल्यूए में शामिल होने से पहले, डॉ पांडे राजनीति विज्ञान विभाग, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर थीं। उन्होंने सेंटर फ़ॉर इंडो-पैसिफ़िक स्टडीज़, स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी प्राप्त की है। उन्होंने 'रोड्स, विंड्स, स्पाइसेज इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन: द मेमोरी एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ़ मेरिटाइम हैरिटेज', केएम पण्णीकर एंड द ग्रोथ ऑफ़ ए मेरिटाइम कॉन्शियसनेस इन इंडिया' और '1982 यूएनसीएलओएस पर्सपेक्टिव्स फ़्रॉम द इंडियन ओशियन' नामक पुस्तकों का सह-संपादन भी किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संवादों-सत्रों में पेपर प्रस्तुत किए हैं और उन्हें बहुत से प्रकाशनों को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है।

भारतीय वैश्विक परिषद्

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत नई दिल्ली- 11001, भारत
टेली.: +91-11-2331 7246-49 | फ़ैक्स: +91-11-2331 1208
www.icwa.in